लखनऊ
शुक्रवार, 14 अगस्त , 2026
वर्ष : 11 | अंक: 345
मूल्य : 1 रुपये
पृष्ठ : 8
UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं, और अनुभव से लोग समझ में आते हैं।

TODAY WEATHER

DAY 32° Hi

NIGHT 28° Low

19 दिन में 19 घंटे भी नहीं चली लोकसभा, राज्यसभा का भी बुरा हाल

नेताओं के झगड़े में टैक्सपेयर्स के 175 करोड़ स्वाहा

लोकसभा की प्रोडक्टिविटी सिर्फ 19% रही, जबकि राज्यसभा 39.17% पर सिमटी

तय करीब 114-114 घंटे के मुकाबले संसद में बेहद कम समय ही कामकाज हो सका

नई दिल्ली, एजेंसी। संसद का मानसून सत्र आज यानी 13 अगस्त 2026 को खत्म हो गया। इस दिन भी दोनों सदनों में भयंकर हंगामा मचा। लोकसभा वंदे मातरम के गायन के बाद स्थगित हो गई और राज्यसभा में करीब 1 घंटे की बहस हुई। इस बार का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। चंदा चोरी, जंतर-मंतर पर हुए छात्रों के प्रदर्शन और लाठीचार्ज, FCRA बिल जैसे कई मुद्दे ऐसे रहे जो कि चर्चा के केंद्र में थे। दोनों सदनों में कामकाज बहुत कम हुआ। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के मुताबिक, इस सत्र में कुल 19 बैठकें प्रस्तावित थीं दोनों को मिलाकर करीब 114-114 घंटे कामकाज होना था, लेकिन हंगामे, नारेबाजी और बार-बार स्थगन के चलते दोनों सदन इस लक्ष्य के आसपास भी नहीं पहुंच पाए। डेटा के मुताबिक इस सत्र में कुल 173 घंटे 10 मिनट बर्बाद हो गए। इस बीच नेताओं की आपसी बहसों के चलते टेक्सपेयर्स आम आदमी का करीब 175 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। जी हां, सदद की कार्यवाही ठीक से न होने के चलते आम-आदमी का पैसा बर्बाद हुआ।

राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी सिर्फ 39.17%

पीआरएस के आंकड़ों के अनुसार राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी इस सत्र में महज 39।17% रही। राज्यसभा में भी करीब 114 घंटे काम होना था, लेकिन कार्यवाही लगभग 37 घंटे 20 मिनट ही चली। करीब 76 घंटे 40 मिनट का समय काम नहीं हो सका। पूरे सत्र के दौरान विपक्षी सांसद लगातार अलग-अलग मुद्दों पर सदन में हंगामा करते रहे। छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा हो या अन्य राजनीतिक विवाद, इन वजहों से सदन की कार्यवाही रोज़ाना कई बार दोपहर या शाम तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सरकार अहम सवालों से बचने की कोशिश कर रही है, जबकि सत्तापक्ष का कहना रहा कि वह चर्चा के लिए हमेशा तैयार था।

लोकसभा की सिर्फ 19% प्रोडक्टिविटी

अगर राज्यसभा का हाल बुरा था, तो लोकसभा की स्थिति उससे भी ज़्यादा खराब रही। पीआरएस के मुताबिक मानसून सत्र 2026 में लोकसभा की प्रोडक्टिविटी घटकर सिर्फ 19% रह गई। सदन सिर्फ 17 घंटे 30 मिनट चला। यानी करीब 96 घंटे 30 मिनट का समय काम नहीं हो सका। लोकसभा में भी हंगामे की यही कहानी दोहराई गई। कई अहम विधेयकों पर चर्चा प्रभावित हुई, यहां तक कि जिन विधेयकों को पारित किया जाना था, उन पर भी ठीक से बहस नहीं हो सकी। सदन की कार्यवाही लगभग हर दिन दोपहर 12 बजे, फिर 2 बजे और कई बार शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। अंतिम दिन भी सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म नहीं हो सका और लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा।

कितने बिल हुए पास

विधायी कामकाज की बात करें तो सरकार के खाते में दोनों सदनों से 12 बिल पास हुए। इनमें सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम, राष्ट्रीय सम्मान, जन्म-मृत्यु पंजीकरण, सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या, MSME, टैक्सेशन, बैंकर्स बुक्स एविडेंस, ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स, केरल नाम परिवर्तन, NCDC और MMDR संशोधन विधेयक शामिल हैं।

12 बिल पास, पर Debate न होने से दुखी: किरेन रिजिजू

केंद्रीय मंत्रीने गुरुवार को कहा कि संसद का हाल ही में खत्म हुआ मॉनसून सत्र विधायी नज़रिए से सफल रहा, जिसमें 12 बिल पास हुए, लेकिन उन्होंने माना कि बहस और चर्चा के मामले में यह सत्र उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। सत्र खत्म होने के बाद मीडिया से बात करते हुए रिजिजू ने कहा कि सरकार ने इस सत्र का आकलन दो अलग-अलग नज़रियों से किया। जहाँ विधायी कामकाज योजना के मुताबिक आगे बढ़ा, वहीं दोनों सदनों में हुए हंगामे ने कुल कामकाज पर असर डाला। रिजिजू ने कहा कि कुल 12 बिल पास हुए, लेकिन हम चर्चा की क्वालिटी से खुश नहीं हैं क्योंकि विपक्ष ने ठीक से बहस नहीं होने दी, खासकर लोकसभा में। मैंने पहली बार देखा है कि विपक्ष चर्चा से बच रहा है। विपक्ष सरकार से जवाब मांगता है और सरकार जवाब देने के लिए बाध्य है। फिर भी, संसद के अंदर हमने देखा कि सरकार खुद चर्चा चाहती थी, जबकि विपक्ष उससे बचने के लिए बहाने बना रहा था। यह संसदीय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने ऐलान किया कि वे न तो चर्चा सुनेंगे और न ही मंत्री का जवाब।

गौरव गोगोई का अमित शाह पर हमला : कुंभकर्ण जैसी नींद में थे गृह मंत्री, संसद से नदारद रहे

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने 13 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना की क्योंकि वे संसद के मॉनसून सत्र के ज़्यादातर समय मौजूद नहीं थे। गोगोई ने कहा कि शाह सत्र खत्म होने से सिर्फ़ दो दिन पहले ही अपनी 'कुंभकर्ण जैसी नींद' से जागे। गोगोई ने सवाल उठाया कि शाह ने असल बहसों में हिस्सा क्यों नहीं लिया, खासकर तब जब विपक्ष जंतर-मंतर पर 20 जुलाई की रैली के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर उनका बयान चाहता था।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए गोगोई ने कहा कि गृह मंत्री 15 दिनों तक गायब रहे और सत्र खत्म होने से दो दिन पहले अपनी 'कुंभकर्ण जैसी नींद' से जागे, यह दावा करते हुए कि वह चर्चा के लिए तैयार हैं। जब असल चर्चा हो रही थी, तब आप कहाँ थे? सभी लोग अपनी राय दे चुके थे; बस आपके बयान का समय था। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह और बातचीत की बात इसलिए कर रही है ताकि गृह मंत्री को विपक्ष की मांगों का जवाब देने से रोका जा सके। गोगोई ने कहा कि लेकिन उन्होंने बयान देने से टाल-मटोल की और बार-बार और बातचीत की मांग की - यह सिर्फ़ सदन से दूर रहने और अपनी ज़िम्मेदारियों से बचने का बहाना था। आख़िरकार, जब लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो रही थी, तब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वहाँ पहुँचे; उन्होंने स्पीकर का संबोधन तक नहीं सुना। गोगोई ने यह भी दावा किया कि मॉनसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार डरी और सहमी हुई थी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह संसदीय कार्यवाही से पूरी तरह नदारद और दूर रहे। उन्होंने कहा कि हमने कई सत्र देखे हैं, लेकिन किसी भी सत्र में सत्ताधारी सरकार को इतना डरा और सहमा हुआ कभी नहीं देखा, जितना इस बार देखा है।

वंदे मातरम का हुआ गान, पीएम मोदी-अमित शाह रहे मौजूद

गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई, जिससे मॉनसून सत्र समाप्त हो गया। यह सत्र विरोध कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के लगातार विरोध और हंगामे के बीच संपन्न हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही राष्ट्रगीत के सभी छह पद बजाए गए, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। जब सदन की संक्षिप्त बैठक हुई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां मौजूद थे। स्पीकर ने सत्र के दौरान सदन के कामकाज और उत्पादकता पर पारंपरिक समापन भाषण नहीं दिया। बिरला ने विपक्ष के सदस्यों से सत्र के दौरान बहस में भाग लेने की बार-बार अपील की थी। हालांकि, विरोध और नारेबाजी जारी रही, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ी। गुरुवार को भी, सदन स्थगित होने से पहले विपक्ष के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

संक्षेप

सरकारी सेवाएं होंगी और आसान, नीति आयोग और 'भाषिणी' ने मिलाया हाथ; अब आपकी अपनी भाषा में मिलेगी हर जानकारी

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार मल्टीलिंगुअल और वॉयस-फर्स्ट एआई तकनीक पर काम कर रही है ताकि शासन और सार्वजनिक सेवाएं ज्यादा समावेशी और आसान बन सकें। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार, इस लक्ष्य के लिए डिजिटल इंडिया 'भाषिणी'डिवीजन डीआईबीडी और नीति आयोग ने भाषिणी फॉर सेवा/संचालन पहल के तहत एक घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का मकसद 'भाषिणी' के मल्टीलिंगुअल एआई इकोसिस्टम का इस्तेमाल करके शासन को ज्यादा समावेशी और सुलभ बनाना है। इसके लिए नीति आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म और सेवाओं में एआई आधारित भाषा तकनीकों को जोड़ा जाएगा। सरकारी बयान में कहा गया, यह साझेदारी नागरिकों को उनकी पसंदीदा भारतीय भाषाओं में सरकारी जानकारी और सेवाओं तक पहुंच दिलाएगी। इससे सरकार और नागरिकों के बीच संवाद मजबूत होगा और सार्वजनिक सेवा वितरण में बहुभाषी संचालन को बढ़ावा मिलेगा। इस साझेदारी के तहत 'भाषिणी' के भाषा अनुवाद एपीआई और रेफरेंस एप्लीकेशन के जरिए नीति आयोग की सेवाओं तक बहुभाषी पहुंच आसान होगी। इसके साथ ही अनुवाद मॉडल के विकास और लगातार सुधार में मदद मिलेगी। भाषा तकनीकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम और संचार वर्कफ्लो में भी जोड़ा जाएगा। इस इको सिस्टम का एक अहम हिस्सा 'स्मृति' है। इसका पूरा नाम सिस्टम फॉर मीटिंग रिकॉर्डिंग, इनफॉर्मेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इंटरफेस है। इसे 'भाषिणी' के साथ मिलकर विकसित किया गया है। 'स्मृति' बैठक के मिनट्स को अपने आप तैयार करेगा और उनका बहुभाषी अनुवाद भी करेगा। इससे सरकारी कामकाज की दक्षता बढ़ेगी और अंतिम व्यक्ति तक शासन ज्यादा समावेशी बनेगा।

लेह में भूकंप के तेज झटके, 5.5 रही तीव्रता, 10 किलोमीटर की गहराई पर था केंद्र

लेह। लेह में गुरुवार सुबह 6 :05 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार, रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5 .5 दर्ज की गई। भूकंप का केंद्र जमीन से सिर्फ 10 किलोमीटर नीचे था और इसका केंद्र बिंदु 36 .881 डिग्री नॉर्थ, 74 .402 डिग्री ईस्ट पर दर्ज किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने 'एक्स' पोस्ट के जरिए बताया कि फिलहाल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। उथला भूकंप होने के कारण झटके काफी तेज महसूस किए गए। उथला भूकंप वह भूकंप है जिसका उद्गम केंद्र पृथ्वी की सतह से 0 से 70 किलोमीटर की गहराई के भीतर होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार भूकंप पृथ्वी की सतह से लेकर 700 किलोमीटर तक की गहराई में आ सकते हैं। यूएसजीएस के आंकड़ों के मुताबिक इस पूरी रेंज को तीन हिस्सों में बांटा गया है, जिमसें उथला, मध्यम और गहरा भूकंप शामिल हैं। उथले भूकंप आमतौर पर ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। इसकी वजह यह है कि इनमें भूकंपीय तरंगों को सतह तक पहुंचने में कम दूरी तय करनी पड़ती है।

जेल में बंद आजम खान से मिले शिवपाल यादव, कहा– सपा सरकार बनी तो उन्हें बनाएंगे गृहमंत्री

आर्यावर्त क्रांति

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने बुधवार को कहा कि अगर 2027 में राज्य में SP की सरकार बनती है, तो जेल में बंद पार्टी नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आज़म खान को गृह मंत्री बनाया जाएगा। साथ ही, उन्होंने सरकार पर आज़म खान के साथ अन्याय करने का आरोप भी लगाया। यादव ने रामपुर ज़िला जेल में खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म से मुलाक़ात के बाद ये बातें कहीं; वहाँ उन्होंने उनके साथ लगभग एक घंटा बिताया।

बैठक के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए यादव ने कहा कि अगर SP सत्ता में आती है, तो वह कथित अन्याय के लिए ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि खान ने जेल से एक संदेश भेजा है जिसमें SP नेताओं से पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करने और 2027 में सरकार बनाने की दिशा में काम करने को कहा गया है। यादव ने कहा कि आज़म खान के साथ बहुत अन्याय हुआ है। जब हमारी सरकार बनेगी, तो हम उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे जिन्होंने यह अन्याय किया है। हम आज़म खान के साथ हुए अन्याय का बदला लेंगे।

उन्होंने आगे कहा कि अगर 2027 में SP की सरकार बनती है, तो खान को गृह मंत्री बनाया जाएगा। यादव ने दावा किया कि खान जेल में बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और आरोप लगाया कि उन्हें ज़मीन पर सोने के लिए मजबूर किया जा रहा है और उन्हें दवाइयाँ और कपड़े भी नहीं दिए जा रहे हैं।

राहुल गांधी को भाजपा की चुनौती : जेपीएससी स्कैम पर ट्वीट नहीं, सीएम हाउस के बाहर धरना दो

नई दिल्ली, एजेंसी। झारखंड भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदित्य साहू ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चुनौती दी कि वे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (JPSC) और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (JSSC)-कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रहे छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर धरना दें। ANI से बात करते हुए, साहू ने गांधी से आग्रह किया कि वे छात्रों के आंदोलन के बारे में सोशल मीडिया पर बयान जारी करने के बजाय हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के खिलाफ सीधे कार्रवाई करें।

साहू ने कहा कि झारखंड सरकार कांग्रेस के समर्थन से चल रही है। वहां छात्र पिछले 20 दिनों से विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी में हिम्मत है, तो उन्हें झारखंड जाकर छात्रों से बात करनी चाहिए। सिर्फ़ ट्वीट करने और बयान देने से काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी वहां समर्थन देकर झारखंड में नौकरियों का सौदा कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी में हिम्मत है, तो उन्हें मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना देना चाहिए, विरोध करना चाहिए और सरकार को चेतावनी देनी चाहिए। उन्हें छात्रों की मांग के अनुसार CBI जांच करवानी चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, तो उन्हें सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए और छात्रों के साथ मिलकर विरोध करना चाहिए। ये बातें संसद में मॉनसून सत्र के आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी सांसदों के बीच हुए जवाबी विरोध-प्रदर्शन के दौरान कही गईं। विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन करते हुए एक खिलौना बंदर दिखाया और नारा लगाया कि 56 इंच का छोटा बंदर, जल्दी आओ सदन के अंदर। गुरुवार को, सत्र के आखिरी दिन कार्यवाही में बाधा डालते हुए, सत्ताधारी BJP और विपक्षी INDIA गठबंधन की ओर से ज़ोरदार नारेबाज़ी और जवाबी विरोध-प्रदर्शन के बीच लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई।

खड़गे की रैली के बाद 'शुद्धिकरण' पर बवाल: प्रियंका गांधी ने पूछा - यह कैसीराजनीति

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने 13 अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद BJP और RSS द्वारा किए गए 'शुद्धिकरण' हवन की आलोचना की। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस कार्यक्रम की निंदा करने और माफ़ी मांगने की मांग की। खरगे ने 8 अगस्त को उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के तहत कांग्रेस की रैली में भाषण दिया। इस घटना पर टिप्पणी करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि यह सोच साफ तौर पर बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को दिखाती है। इसे खारिज किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री को इसकी निंदा करनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए।

कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने भी BJP और RSS की आलोचना की और सत्ताधारी पार्टी पर ऐसी विचारधारा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जो समानता के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि BJP-RSS सरकार और उनकी विचारधारा के लिए यह शर्म की बात है कि एक तरफ तो वे 'तिरंगा यात्रा' निकालने और ऐसी पब्लिसिटी करने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे नेता और विपक्ष के नेता के मामले में समानता के उस सिद्धांत का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, जिसकी गारंटी हमारे संविधान ने दी है और जिसे देश और दुनिया मानती है।

शैलजा ने इस घटना पर कोई कार्रवाई न करने के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को देखिए, यह बीजेपी शासित राज्य है जहाँ वे बड़े-बड़े दावे करते हैं; ज़रा उस जगह के बारे में सोचिए जहाँ खड़गे जी और हम सबने रैली की थी; वे वहाँ 'शुद्धिकरण' कर रहे हैं। यह किस तरह का 'शुद्धिकरण' है? असल में उत्तराखंड को शुद्धिकरण की ज़रूरत है - ऐसी विचारधारा, ऐसी सोच और ऐसी घटिया मानसिकता से शुद्धिकरण। उत्तराखंड को इस बात से मुक्त करने की ज़रूरत है कि ऐसे लोग सत्ता में हैं, फिर भी ऐसी घटनाओं पर कोई कार्रवाई नहीं करते। इस बीच, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कथित घटना की निंदा की और कहा कि बीजेपी ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करेगी।

शौर्य चक्र विजेता की विधवा ने पेंशन के लिए 26 साल किया संघर्ष, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद मिला इंसाफ

नई दिल्ली, एजेंसी। सरकारी सिस्टम की लेटलतीफी और संवेदनहीनता कभी-कभी उन परिवारों को भी नहीं बख्शती, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया हो। इसका एक ताजा और दिल दहला देने वाला उदाहरण शौर्य चक्र विजेता शहीद मोहन सिंह की विधवा का 26 साल लंबा संघर्ष है। देश के लिए जान कुर्बान करने वाले पति की 'स्पेशल फैमिली पेंशन पाने के लिए एक पत्नी को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ीं। आखिरकार, 26 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया, तब जाकर शहीद की विधवा को उनका हक मिल सका।

जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स में ओवरसियर के पद पर तैनात मोहन सिंह सीमा पर एक बेहद अहम सड़क निर्माण कार्य के इंचार्ज थे। 10 जुलाई 2000 को जब वह अपनी टीम के साथ काम कर रहे थे, तभी अचानक पहाड़ी से भारी मलबे के साथ एक बड़ा पत्थर नीचे गिरने लगा। खतरे को भांपते हुए मोहन सिंह ने अपनी जान की परवाह न करते हुए सभी मजदूरों को सुरक्षित वहां से हटा दिया, लेकिन वह खुद उस मलबे की चपेट में आ गए और वीरगति को प्राप्त हुए। उनके इस अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए केंद्र सरकार ने साल 2001 में उन्हें मरणोपरांत प्रतिष्ठित 'शौर्य चक्र से सम्मानित किया था। मोहन सिंह की शहादत के बाद, उनकी विधवा को 'सीसीएस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन (स्पेशल फैमिली पेंशन) मिलनी चाहिए थी, जिसकी वह हकदार थीं। लेकिन, सरकार ने सिर्फ यह तर्क देकर उनका दावा खारिज कर दिया कि उन्हें 'वर्कमेन कंपनसेशन एक्ट के तहत मुआवजा दिया जा चुका है, इसलिए नियमों के अनुसार उन्हें लिबरलाइज्ड पेंशन का लाभ नहीं दिया जा सकता। इसके बाद उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने माना कि वह एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन की हकदार हैं, लेकिन बकाया राशि का भुगतान याचिका दायर करने की तारीख से करने का आदेश दिया।

पति के साथ इस महिला की दरिंदगी सुनकर कांप जाएंगे आप, हत्या के बाद लाश को भी न बख्शा, 45 दिन तक किया ये काम

आर्यावर्त संवाददाता

आगरा। आगरा के थाना सिकंदरा स्थित रेणुका धाम में पति की हत्या कर शव को बाथरूम में दफनाने वाली रूबी शर्मा के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर ली है। इसमें विवेचक ने फोरेंसिक साक्ष्य जुटाने से लेकर मृतक की बेटियों और भाई के बयान को अहम माना है। कंकाल सुरेंद्र शर्मा का था? इसकी पुष्टि के लिए डीएनए जांच होगी। कोर्ट से इसकी अनुमति मिल गई है। बेटियों ने मां के खिलाफ बयान दिए हैं।

तीन जुलाई को हत्याकांड सामने आया था। रेणुका धाम निवासी सुरेंद्र शर्मा 18 मई से लापता थे। 26 मई को गुमशुदगी दर्ज कराई। परिजन ने तलाश की लेकिन वो मिले नहीं। सुरेंद्र पत्नी रूबी शर्मा, 14 और 9 वर्षीय बेटियों के अलावा मां के साथ रहते थे। बड़े भाई अनिल शर्मा ने सिकंदरा पुलिस को भाई की हत्या की जानकारी दी थी।

रूबी ने पूछताछ में बताया था कि पति शराब पीकर मारपीट करता था। परेशान होकर उसने खीर में जहर मिलाकर हत्या कर दी। पति की मौत के बाद शव को घर के बाथरूम में दफन कर दिया। बाथरूम के फर्श का निर्माण करा दिया था। पुलिस ने मजदूरों से फर्श को खुदवाया था। कंकाल बरामद किया था। मौके से मिले कड़े और रुद्राक्ष की माला से मृतक के सुरेंद्र शर्मा होने का दावा किया गया। सुरेंद्र इन्हें पहना करते थे।

पुलिस से बोली-पति ने कर ली थी आत्महत्या

आरोपी रूबी को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो वह बार-बार बयान बदलने लगी। पहले उसने नींद की गोली देने की बात कही। फिर कहा कि पति ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घबराकर उसने शव को दफना दिया।

उसने कहा कि बाथरूम का फर्श कमरे के फर्श से दो से तीन फीट नीचे था, इसलिए शव को उसमें डाल दिया। इसके बाद मिट्टी लाकर डाल दी और मिस्त्री बुलाकर फर्श पक्की करवा दी। इससे किसी को शक नहीं हुआ।

वह घर में भी आराम से रह रही थी। हालांकि, पुलिस को शक है कि घटना में कोई और भी शामिल हो सकता है। एक अकेला व्यक्ति इस पूरी घटना को अंजाम नहीं दे सकता। मौके पर पहुंची पुलिस ने बाथरूम का फर्श खोदकर कंकाल बरामद किया

24 साल पहले भरतपुर से आगरा आया था परिवार

पुलिस के अनुसार, मूलरूप से भरतपुर के रंजीत नगर निवासी राधेश्याम शर्मा एक इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पद पर कार्यरत थे। 24 साल पहले सेवानिवृत्त होने के बाद आगरा आ गए थे। सिकंदरा के दहतोरा स्थित रेणुका धाम कॉलोनी में रहने लगे। 14 साल पहले उनकी मौत हो गई थी।

सुरेंद्र उनका छोटा बेटा था। बड़े बेटे अनिल ऑटो चालक हैं और वायु विहार, शाहगंज में रहते हैं। सुरेंद्र रेणुका धाम कॉलोनी में रहते थे। उनकी शादी 16 साल पहले रूबी से हुई थीं। दो बेटियां प्राची (15) और सिद्धि (9) हैं। सुरेंद्र की मां कमला भी साथ ही रहती थीं।

पुलिस की पूछताछ में पता चला कि सुरेंद्र की मां को पति की पेंशन के 32 हजार रुपये मिलते थे। रूबी डेबिट कार्ड और पासबुक अपने पास रखती थी। पेंशन की रकम से वह जेठ अनिल को 10 हजार रुपये देती थी। जून में रूबी ने अनिल को पेंशन की रकम नहीं दी थी।

नीचे दफन था पति, ऊपर रोज नहाती थी रूबी

पति सुरेंद्र शर्मा की हत्या के बाद रूबी ने शव को न सिर्फ बाथरूम में दफनाया था, बल्कि रोज लाश के ऊपर ही नहाती थी। वह नियमित बाथरूम का इस्तेमाल कर रही थी। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि जब पड़ोसी सुरेंद्र के बारे में पूछते तो परेशान होने का नाटक करती थी।

बेटियों ने मां के खिलाफ दिए बयान

डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि मृतक की डीएनए जांच के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने अनुमति दे दी है। मृतक का उसकी मां के डीएनए से मिलान कराया जाएगा। वहीं आरोपी पत्नी जेल में है। भाई और मां ने रूबी के खिलाफ बयान दिए। मासूम बेटियां ने भी बयान दिए। बताया कि 18 मई की सुबह मां ने ताऊ को फोन किया। उनसे कहा कि पुलिस आने वाली है। मां ने दादी और उन्हें घर के बाहर बैठा दिया। बाहर से ताला लगा दिया था। पापा घर में बेड पर पड़े थे। दादी और उन्हें ताऊ के साथ भेज दिया। कुछ दिन बाद मां भी ताऊ के घर आ गईं। लौटने पर बाथरूम का फर्श ऊंचा मिला। मामले में चार्जशीट जल्द दाखिल की जाएगी।

कलह बनी काल

पुलिस के अनुसार, सुरेंद्र नींद की गोलियां खाता था। रूबी ने 18 मई को उसको खीर में मिलाकर नींद 20 से ज्यादा गोलियां दे दीं, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में उसने शव को बाथरूम में दफना दिया। वह पति की हत्या के बाद जितने दिन घर में रही, उसी बाथरूम का इस्तेमाल करती रही। पड़ोसियों के पूछने पर रोने लगती थी।

कड़े और माला से हुई शिनाख्त

पुलिस ने सुरेंद्र का शव बरामद करने के लिए बाथरूम का फर्श खोदा। अंदर कंकाल निकला और कपड़े भी गल चुके थे। हाथ में कड़ा और गले में रुद्राक्ष की माला मिली। सामान देखते ही परिजन ने पहचान कर ली।

बिजली कनेक्शन से वंचित प्राथमिक विद्यालय, भीषण गर्मी में बच्चों की पढ़ाई पर सवाल

सुल्तानपुर। विकासखंड कूरेभार क्षेत्र के ग्राम पंचायत ढेसरुआ स्थित प्राथमिक विद्यालय इन दिनों बुनियादी सुविधाओं को लेकर सवालों के घेरे में है। आरोप है कि विद्यालय की 13 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक विद्यालय में विद्युत कनेक्शन नहीं कराया जा सका है।स्थानीय स्तर से मिली जानकारी के अनुसार यह प्राथमिक विद्यालय वर्ष 2013 में शुरू हुआ था, लेकिन वर्ष 2026 अगस्त आज तक यहां बिजली कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी है। ऐसे में भीषण गर्मी के बीच छोटे-छोटे बच्चों को बिना बिजली कनेक्शन के विद्यालय में पढ़ाई करनी पड़ रही है। जहाँ एक ओर प्रदेश सरकार सरकारी विद्यालयों में बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है।

पशपालकों के लिए संजीवनी बनी 1962 मोबाइल वेटरनरी यूनिट

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

अखंडनगर/सुलतानपुर। प्रदेश सरकार द्वारा पशुपालकों के हित में शुरू की गई 1962 मोबाइल वेटरिनरी यूनिट ग्रामीण क्षेत्रों में वरदान साबित हो रही है इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करते ही वेटरनरी टीम पशुओं के इलाज के लिए सीधे घर पहुंच रही है जिससे पशुपालकों को समय, धन, और परेशानियों से बड़ी राहत मिल रही है। ताजा मामला अखंड नगर ब्लॉक के बंनगावडीह गांव का सामने आया है गांव के निवासी अमरजीत ने बताया कि उनकी भैंस कई दिनों से गंभीर रूप से बीमार थी कई निजी डॉक्टर से इलाज करने के बावजूद कोई सुधार न होता देख अमरजीत निराश हो चुके थे इसी बीच किसी ने उन्हें 1962 टोल फ्री नंबर पर कॉल करने की सलाह दी टीम द्वारा किए गए उपचार के बाद अब भैंस की हालत में काफी सुधार हो चुका है अमरजीत ने बताया यदि यह सेवा ना होती तो शायद हमारी भैंस बच नहीं पाती। सरकार की यह सुविधा हमारे जैसे पशुपालकों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में पशुधन ही आम लोगों की आय का प्रमुख साधन होता है ऐसे में सरकार की ये पहल पशुपालकों के चेहरे पर मुस्कान ला रही है। जिले में सैकड़ो पशुपालक 1962 सेवा का लाभ उठाकर अपने बीमार पशुओं का सफल उपचार करा रहे हैं 1962 मोबाइल वेटरनरी यूनिट सेवा न केवल पशुपालकों को राहत दे रही है बल्कि पशुधन संरक्षण में भी बड़ी भूमिका निभा रही है।

तिरंगा यात्रा में संवेदनहीनता

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। जनपद में घर-घर तिरंगा यात्रा के दौरान प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों की भारी संवेदनहीनता और निष्ठुरता का मामला सामने आया है। देशभक्ति के नाम पर आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल होने आए विभिन्न विद्यालयों के सैकड़ों मासूम बच्चे तिकुनिया पार्क में घंटों तक भारी धूप और उमस में खड़े रहने को मजबूर हुए। कड़ाके की धूप और भीषण गर्मी के कारण बच्चों की हालत बिगड़ गई। उचित व्यवस्था (जैसे छाया और पानी) न होने के कारण कई स्कूली बच्चे चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। मौके पर मौजूद साथी छात्रों और शिक्षकों ने किसी तरह बच्चों को संभाला।

एक तरफ जहां मासूम बच्चे धूप में तड़प रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कार्यक्रम का मुख्य मंच पूरी तरह से अधिकारियों से रहित था। बच्चों को समय पर बुलाकर खुद अधिकारी नदारद रहे, जो प्रशासन की घोर लापरवाही और निष्ठुरता का जीता-जागता उदाहरण है। देशभक्ति के इस उत्सव में बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ताक पर रखकर किया गया यह आयोजन अब स्थानीय जनता के बीच आक्रोश का कारण बन रहा है।

गोरखपुर में शटरिंग खोलते समय करंट की चपेट में आया मजदूर, मौके पर मौत

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

गोरखपुर। बड़गों वार्ड नंबर 11 में गुरुवार सुबह शटरिंग खोलते समय एक मजदूर ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। करंट लगते ही मजदूर बुरी तरह झुलस गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। रामगढ़ताल थाना पुलिस मजदूर की पहचान कोशिश में जुटी है। अखिल आनंद पाठक के मकान की दूसरी मंजिल पर छत की शटरिंग लगी थी। गुरुवार सुबह मजदूर शटरिंग खोलने में जुटे थे। इसी दौरान ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन की चपेट में 45 वर्षीय मजदूर आ गया।

तेज करंट लगते ही वह वहीं गिर पड़ा। जब तक आसपास के लोग कुछ समझ पाते, उसकी मौत हो चुकी थी। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जुट गए। सूचना पर आजाद नगर चौकी पुलिस भी पहुंची। एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि मजदूर की पहचान नहीं हो पाई है।

पहले भी हो चुके हैं हादसे

इसी 11 हजार वोल्ट के तार से पहले भी हादसे हो चुके हैं। जुलाई-अगस्त 2015 में राजकिशोर यादव के मकान के निर्माण के दौरान एक मजदूर की 11 हजार वोल्ट की चपेट में आने से मौत हो गई थी। इस घटना के 10 साल बाद, 2025 में, दो मकान छोड़कर उपेंद्र यादव के मकान में काम करते समय एक अन्य मजदूर इसी लाइन की चपेट में आकर झुलस गया था।

पंचायत सहायक व सचिवों का एकदिवसीय प्रशिक्षण संपन्न

सुल्तानपुर। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत लम्भुआ ब्लॉक में पंचायत सहायक एवं पंचायत सचिवों के लिए एकदिवसीय विकासखंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का विषय ओएसआर पोर्टल, रिवेन्यू जेनरेशन एंड सर्विस डिलीवरी रहा कार्यक्रम विकासखंड लम्भुआ के सभागार में हुआ प्रशिक्षण सेवानिवृत्त डीपीआरओ एवं बीडीओ नीलिमा गुप्ता ने दिया उन्होंने पंचायत सहायकों एवं पंचायत सचिवों को ओएसआर पोर्टल के संचालन, राजस्व सृजन के तरीकों और बेहतर सेवा डिलीवरी के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान ब्लॉक के दर्जनों पंचायत सहायक उपस्थित रहे वहीं ब्लॉक के सचिव राज बहादुर, रामराज, प्रेम लता, शारदा दूबे, राज लक्ष्मी एवं पंचायत सहायक पर्यावरण संरक्षक अजयकांत तिवारी प्रयागराज भी मौजूद रहे प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और पोर्टल पर डेटा फीडिंग के संबंध में भी महत्वपूर्ण टिप्स दिए गए।

तिरंगा यात्रा से पहले सिलिंडर फटने से दहल उठा बुलंदशहर का काला आम चौराहा, शुभारंभ को पहुंचने वाले थे मंत्री

आर्यावर्त संवाददाता

बुलंदशहर। तिरंगा यात्रा के शुभारंभ से पहले तैयारी के दौरान गुरुवार सुबह कालाआम चौराहा पर गुब्बारे भरते समय हीलियम गैस का सिलिंडर अचानक फट गया। हादसे में दो लोग घायल हो गए। इसमें गंभीर रुप से घायल एक युवक को मेडिकल कालेज की इमरजेंसी से हायर सेंटर दिल्ली रेफर किया गया, जबकि एक घायल का वार्ड में उपचार चल रहा है।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कालाआम चौराहा से गुरुवार सुबह साढ़े नौ बजे भाजपा की विशाल और भव्य तिरंगा यात्रा का शुभारंभ होना था। इसके लिए शहर में कई स्थानों पर टैंट लगाकर सुंदर गेट बनाए गए हैं। गुरुवार की सुबह गुब्बारे से सजावट का काम चल रहा था और शहर के शिकारपुर बाईपास चीरघर निवासी 41 वर्षीय राकेश पुत्र रामगोपाल और शहर के मुहल्ला साठा गड़रियों वाली गली निवासी राजेश पुत्र राम सिंह हीलियम सिलिंडर से गुब्बारे भर रहे थे।

इसी दौरान हीलियम गैस का सिलिंडर अचानक तेज आवाज के साथ फट गया। सिलिंडर फटते ही कार्यक्रम में अफरातफरी मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे। दुर्घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने दोनों घायलों को तुरंत कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कालेज से संबद्ध जिला अस्पताल की इमरजेंसी पहुंचाया। यहां गंभीर हालत के चलते राकेश को हायर सेंटर दिल्ली रेफर कर दिया। चिकित्सकों ने बताया कि राकेश ही हालत नाजुक है, इसलिए रेफर करना पड़ा, जबकि राजेश का वार्ड में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। सिलिंडर बुरी तरह ध्वस्त हो गया।

हीलियम गैस पर विशेषज्ञ की राय

उधर, मेडिकल कालेज में इमरजेंसी के हेड प्रोफेसर डा. रोहित वार्ष्णेय का कहना है कि गुब्बारों में हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि यह हवा से बहुत हल्की होती है, जिस वजह से गुब्बारा आसमान में ऊपर उड़ने लगता है। हीलियम एक अक्रिय और अज्वलनशील गैस है, जो आग नहीं पकड़ती। यह इंसानों और प्रकृति के लिए पूरी तरह सुरक्षित, विषैली और गंधहीन होती है। यह ज्वलनशील नहीं होती है। इससे आग लगने या धमाका होने का खतरा नहीं रहता है।

12 लोगों को किया घायल, एक महिला की मौत... मुरादाबाद में खूंखार तेंदुओं का खूनी तांडव!

आर्यावर्त संवाददाता

मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के ठाकुरद्वारा तहसील इलाके में तेंदुओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे दर्जनों गांवों के ग्रामीणों में भारी दहशत है। तेंदुओं के हमलों में अब तक 12 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं, जबकि एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीमें बड़े पैमाने पर कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। थर्मल इमेजिंग और ड्रोन कैमरों की मदद से तेंदुओं की मूवमेंट पर पैनी नजर रखी जा रही है।

इलाके में 18 से अधिक पिंजरे लगाए जा चुके हैं, जिनमें से अब तक दो तेंदुए, जिसमें एक लालापुर और दूसरा बलिया गांव से ट्रैप किए जा चुका है। प्रशासन ने ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए 60 से 70 कर्मचारियों की फौज मैदान में उतारी है। साथ ही वाइल्डलाइफ SOS (आगरा) और WWF की विशेषज्ञ टीमों को भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल किया गया है। अधिकारियों द्वारा गांव-गांव चौपाल लगाकर लोगों को अकेले खेतों में न जाने, समूह में काम करने और लाठी-डंडे साथ रखने की सख्त हिदायत दी जा रही है। प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद और घायलों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रशासन का सर्च ऑपरेशन और बचाव की तैयारियां

तेंदुओं को पकड़ने के लिए वन विभाग ने संभल, रामपुर, अमरोहा और बिजनौर से अतिरिक्त बल तैनात किया है। थर्मल ड्रोन और ट्रैप केज की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। जिलाधिकारी और DFO के अनुसार, अब तक दो तेंदुए पकड़े जा चुके हैं, जबकि अन्य की तलाश जारी है। क्षेत्र पंचायत और नगर पालिकाओं के माध्यम से 10 नए पिंजरे मंगवाए गए हैं। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए कांवड़ पथ पर विशेष मोबाइल वैन, लाइटिंग और पुलिस पिकेट की व्यवस्था की गई है, ताकि किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रशासन और वन विभाग ने ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चलाया है, लोगों से अपील की गई है कि वे रात के समय खेतों में बिल्कुल न जाएं और दिन में भी 7 से 8 लोगों के समूह में ही काम पर निकलें। खेतों में काम के दौरान धुआं करने, आपस में बातचीत करते रहने और लाठी-डंडे साथ रखने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, मवेशियों को खेतों की बजाय सुरक्षित घरों के भीतर बांधने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि तेंदुओं को शिकार का मौका न मिले।

राहत सहायता और घायलों का मुफ्त इलाज

तेंदुओं के हमलों में घायल हुए सभी नागरिकों के इलाज का पूरा खर्च प्रशासन द्वारा उठाया जा रहा है। हमले में जान गंवाने वाली महिला के परिजनों को दैवीय आपदा कोष से आर्थिक सहायता राशि प्रदान कर दी गई है। इसके अलावा, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नेताओं ने भी प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। सपा विधायक नवाब जान खान ने घायलों को 25-25 हजार रुपये और मृतका संतोष के परिवार को 50 हजार रुपये की निजी आर्थिक मदद सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। तेंदुओं की लगातार मौजूदगी को देखते हुए डिलारी और आसपास के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस टीमें लाउडस्पीकर के जरिए मुनादी करवाकर लोगों को सतर्क रहने और घरों के भीतर रहने की अपील कर रही हैं। दूसरी ओर, बार-बार हो रहे हमलों से ग्रामीणों का गुस्सा भी भड़क रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि वन विभाग ने जल्द ही बचे हुए तेंदुओं को रेस्क्यू नहीं किया, तो वे किसानों और ग्रामीणों को साथ लेकर उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे।

गांव की बेटी ने रचा स्वर्णिम इतिहास, 91.25 प्रतिशत अंकों से दो गोल्ड मेडल पर कब्जा

आर्यावर्त संवाददाता

बल्दीराय/सुलतानपुर। बल्दीराय तहसील क्षेत्र के डेहरियावां गांव की बेटी मुस्कान सिंह ने अपनी प्रतिभा का परचम लहराते हुए क्षेत्र और जिले का नाम रोशन किया है। डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या की बीए परीक्षा में 3600 में 3285 अंक यानी 91.25 प्रतिशत अंक हासिल कर मुस्कान ने विश्वविद्यालय की पदक तालिका में अपना स्थान बनाया। उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि पर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने उन्हें दो स्वर्ण पदकों से सम्मानित किया।

मुस्कान का चयन बीए पाठ्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कुलपति स्वर्ण पदक तथा सेठ हारिका दास झुनझुनवाला स्वर्ण पदक के लिए हुआ। समारोह में स्वर्ण पदक प्राप्त करते ही परिवार और क्षेत्र के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। डेहरियावां निवासी अखंड प्रताप सिंह की पुत्री मुस्कान ने कक्षा छह से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई श्रीमती सुंदरा देवी बलदेव सिंह इंटर कॉलेज, हलियापुर से पूरी की। इसके बाद श्री बलदेव सिंह भालेसुलतान महाविद्यालय से बीए की शिक्षा हासिल कर विश्वविद्यालय स्तर पर यह शानदार सफलता अर्जित की। मुस्कान की उपलब्धि पर महाविद्यालय के प्रबंधक एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख रवींद्र प्रताप सिंह, निदेशक अमितेश सिंह और परिजनों ने बधाई दी। ग्रामीण परिवेश से निकलकर विश्वविद्यालय में स्वर्णिम उपलब्धि हासिल करने वाली मुस्कान सिंह क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बन गई हैं।

यूपी में जमीन विवादों पर योगी सरकार का निशाना, 7 महीने में निपटाए गए 10.96 लाख से ज्यादा मामले

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार की त्वरित न्याय और जनसमस्याओं के प्रभावी निस्तारण की नीति के तहत राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों के निस्तारण की प्रक्रिया को लगातार तेज किया जा रहा है। शासन स्तर से की जा रही नियमित मॉनिटरिंग और विशेष अभियानों का असर राजस्व वादों के निस्तारण के आंकड़ों में दिखाई दे रहा है।

सीमांकन/पैमाइश से संबंधित धारा-24 के तहत 31 दिसंबर 2025 तक 28,556 वाद विचाराधीन थे। 1 जनवरी से 31 जुलाई 2026 तक 91,472 नए वाद आए, जिनमें से 39,645 वादों का निस्तारण किया गया। वर्तमान में 80,383 वाद विचाराधीन हैं। पांच वर्ष से अधिक पुराने लंबित वादों की संख्या महज 24 है। धारा-24 के तहत सबसे अधिक विचाराधीन वादों वाले जिलों में प्रयागराज, प्रतापगढ़, लखनऊ, अमेठी और मथुरा शामिल हैं।

नामांतरण/दाखिल-खारिज से संबंधित धारा-34 में भी बड़े स्तर पर निस्तारण किया गया। 31 दिसंबर 2025 तक 48,910 वाद विचाराधीन थे। 1 जनवरी से 31 जुलाई 2026 के बीच 14,70,133 वाद आयोजित हुए, जिनमें से 10,96,814 वादों का निस्तारण किया गया। वहीं, 45 दिन से अधिक अवधि से लंबित नामांतरण वादों के निस्तारण के लिए 15 से 25 जून 2026 तक चलाए गए विशेष अभियान में ही 2,21,667 वादों का निस्तारण किया गया।

भू-उपयोग परिवर्तन के मामलों में भी तेजी

धारा-80 के तहत भू-उपयोग परिवर्तन से जुड़े मामलों में 1 जनवरी से 31 जुलाई 2026 तक 28,797 वाद आए, जबकि 49,855 वादों का निस्तारण किया गया। पांच वर्ष से अधिक पुराने लंबित वादों की संख्या शून्य दर्ज की गई है।

पुराने मामलों के निस्तारण पर विशेष जोर

योगी सरकार द्वारा राजस्व न्यायालयों में पुराने और लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि विशेष अभियान, नियमित समीक्षा और तकनीक आधारित मॉनिटरिंग के माध्यम से लंबित वादों के निस्तारण की गति बढ़ी है। योगी सरकार का लक्ष्य है कि लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण, आमजन को समयबद्ध न्याय और राजस्व संबंधी मामलों में पारदर्शी एवं सुगम व्यवस्था उपलब्ध कराना है।

लोनी में ए.के. शर्मा ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा, बोले- तिरंगा अब जन-जन की भावना और राष्ट्रभक्ति का जन आंदोलन

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने लोनी विधायक नन्द किशोर गुर्जर के साथ खन्ना नगर, लोनी में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, युवाओं और कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। तिरंगा यात्रा के दौरान पूरा क्षेत्र राष्ट्रभक्ति और देशप्रेम के नारों से गूंजता रहा।इस अवसर पर ए.के. शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के गौरव, सम्मान और स्वाभिमान को नई ऊंचाई देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तिरंगा अब केवल राष्ट्रीय ध्वज नहीं, बल्कि जन-जन की भावना और राष्ट्रभक्ति का जन आंदोलन बन चुका है। उन्होंने कहा कि देश की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को सम्मान देते हुए सरकार सबका विकास और सबकी समृद्धि के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है।विपक्ष पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास विकास का कोई स्पष्ट एजेंडा नहीं है और वह केवल विरोध की राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के सम्मान और तिरंगे के प्रति प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखे। राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि यदि उन्हें देश के विश्वविद्यालयों और युवाओं से इतना ही लगाव था तो उन्होंने विदेश में पढ़ाई क्यों की। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग यदि गांव, गरीब और आम परिवारों के बच्चों के संघर्ष को करीब से समझते तो छात्रों की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझ पाते।शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय प्रयागराज स्थित लोक सेवा आयोग जैसी संस्थाओं में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के आरोप सामने आते रहे, जबकि वर्तमान सरकार में पारदर्शिता और सुशासन को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान गाजियाबाद समेत प्रदेश के अनेक शहर कुशासन और अव्यवस्थाओं से जूझते रहे।

युवाओं पर भरोसा, ऐश्वर्य राज सिंह को मिली यूपी की कमान, लखनऊ पहुंचने पर भव्य स्वागत

लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ऐश्वर्य राज सिंह के प्रथम लखनऊ आगमन पर गुरुवार को प्रदेश मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह की ओर से युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की नीति के तहत ऐश्वर्य राज सिंह को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद उनके स्वागत को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आया। प्रदेश मुख्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया और फूल-मालाओं तथा पुष्पवर्षा से अभिनंदन किया। इस दौरान पूरा परिसर चौधरी चरण सिंह अमर रहें, चौधरी अजित सिंह अमर रहें और जयंत चौधरी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा।ऐश्वर्य राज सिंह के लखनऊ आगमन पर चारबाग रेलवे स्टेशन से ही स्वागत कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो गया

मायावती ने एफसीआरए संशोधन विधेयक को लेकर सत्ता-विपक्ष पर साधा निशाना, कहा- संसद में राजनीतिक स्वार्थ की लड़ाई से जनता रहे सचेत

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने एफसीआरए संशोधन विधेयक को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मुद्दे का सत्ता और विपक्ष ने जरूरत से ज्यादा राजनीतिकरण कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार विधेयक को अति-महत्वपूर्ण बताते हुए जल्द पारित कराना चाहती थी, लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते इसे बिना प्रारंभिक चर्चा के संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया।मायावती ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल एफसीआरए संशोधन विधेयक को अल्पसंख्यक विरोधी बताते हुए इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार विदेश से मिलने वाली फंडिंग के उपयोग में कथित भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इसमें कठोर बदलाव की जरूरत बता रही है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के रुख से स्पष्ट है कि विधेयक का राजनीतिकरण अधिक हो गया है।उन्होंने विपक्ष की रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि विपक्ष विधेयक को संसद में पेश किए जाने के दौरान सदन चलने देता और उसकी कमियों को सदन में उजागर करता तो देश को उसकी वास्तविक जानकारी मिलती। इसके बजाय विपक्ष ने संसद की कार्यवाही बाधित की। मायावती ने दावा किया कि विपक्ष के संसद न चलने देने के कारण कई अन्य विधेयक भी सरकार ने कम समय में पारित करा लिए और इसका सरकार को राजनीतिक लाभ मिल रहा है।बसपा अध्यक्ष ने कहा कि ऐसी स्थिति में विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उन्होंने आरोप लगाया कि या तो विपक्ष और सरकार के बीच अंदरूनी मिलीभगत है या फिर विपक्ष जेन-जी के वोटों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए देश के अन्य महत्वपूर्ण सवालों को नजरअंदाज कर रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं से जुड़े मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जनहित के अन्य विषयों को भी समान प्राथमिकता मिलनी चाहिए।मायावती ने अयोध्या स्थित राममंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी संसद में उठाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि इस विषय पर संसद में चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते इसे पीछे कर दिया।उन्होंने देश की जनता से सत्ता और विपक्ष के बीच संसद सत्र के दौरान चल रही राजनीतिक खींचतान को लेकर सचेत रहने की अपील की। मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी डॉ. भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा और 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' के सिद्धांतों के आधार पर जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में देश और आम जनता के हित से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाना समय की आवश्यकता है।

यूपी रेरा ने रियल एस्टेट एजेंटों को नियमों का पाठ पढ़ाया

लखनऊ। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) की ओर से गुरुवार को रेरा मुख्यालय लखनऊ में रियल एस्टेट एजेंटों के लिए वेबिनार आयोजित किया गया। अध्यक्षता यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने की। वेबिनार में एजेंटों को रेरा के नियमों, आवश्यक दस्तावेजों, विज्ञापन संबंधी प्रावधानों, लेनदेन का रिकॉर्ड रखने और समय से जानकारी उपलब्ध कराने से जुड़े नियमों की विस्तार से जानकारी दी गई।कार्यक्रम की शुरुआत यूपी रेरा के सचिव महेंद्र वर्मा के स्वागत संबोधन से हुई। उन्होंने वेबिनार के उद्देश्य और रियल एस्टेट एजेंटों के लिए इसके महत्व पर प्रकाश डाला। अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा कि रियल एस्टेट कारोबार में एजेंटों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि एजेंट नियमों के अनुरूप और पूरी जानकारी के साथ काम करेंगे तो इससे खरीदारों का भरोसा बढ़ेगा तथा रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता मजबूत होगी।

संक्षेप

हर घर तिरंगा' अभियान के तहत कैप्टन मनोज पांडेय चौराहे पर स्वच्छता श्रमदान, शहीद को किया नमन

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत शहीदों और महापुरुषों की प्रतिमाओं तथा स्मारक स्थलों पर स्वच्छता श्रमदान और माल्यार्पण कार्यक्रमों की श्रृंखला जारी है। इसी क्रम में गुरुवार सुबह गोमती नगर स्थित परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडेय चौराहे पर कार्यक्रम आयोजित किया गया।भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. नीरज सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कैप्टन मनोज पांडेय की प्रतिमा और आसपास के परिसर में स्वच्छता श्रमदान किया। इसके बाद उन्होंने शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके अदम्य साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धापूर्वक नमन किया। कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने भी उत्साहपूर्वक सहभागिता की।डॉ. नीरज सिंह ने कहा कि 'हर घर तिरंगा' अभियान राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय स्वाभिमान और वीर शहीदों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने वाला जनअभियान है। देश की रक्षा और सम्मान के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर सपूतों की स्मृतियों को संजोना और उनके स्मारक स्थलों की गरिमा बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है।उन्होंने कहा कि तिरंगा देश की आन, बान और शान के साथ राष्ट्रीय एकता और स्वाभिमान का प्रतीक है। कैप्टन मनोज पांडेय जैसे वीर सपूतों का जीवन देश को सदैव सर्वोपरि रखने की प्रेरणा देता है। 'हर घर तिरंगा' अभियान के माध्यम से विशेष रूप से युवा पीढ़ी तक वीर शहीदों के शौर्य, त्याग और बलिदान का संदेश पहुंचाना जरूरी है।भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं और नागरिकों से अपील की कि वे 'हर घर तिरंगा' अभियान में पूरे उत्साह के साथ भाग लें, अपने घरों पर गर्व के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराएं और अपने आसपास स्थित शहीदों तथा महापुरुषों के स्मृति स्थलों की गरिमा बनाए रखने में योगदान दें।कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने स्वच्छता श्रमदान में भाग लिया तथा अमर शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडेय को श्रद्धासुमन अर्पित कर उनके राष्ट्र के प्रति सर्वोच्च बलिदान को नमन किया।

आयुष्मान योजना में मरीजों की सुरक्षा से समझौता पड़ा भारी, प्रदेश के 184 निजी अस्पताल डी-इम्पैनल

लखनऊ। आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों की सुरक्षा और इलाज की गुणवत्ता के मानकों का पालन नहीं करने वाले प्रदेश के 184 निजी अस्पतालों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। इन अस्पतालों को आयुष्मान योजना से डी-इम्पैनल कर दिया गया है। अब इन अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत मरीजों को कैशलेस इलाज की सुविधा नहीं मिल सकेगी।उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि भारत सरकार की ओर से आयुष्मान योजना से संबद्ध अस्पतालों के लिए सुरक्षा और गुणवत्ता से जुड़े मानकों को और सख्त किया गया है। इसके बाद प्रदेश में योजना से जुड़े सभी अस्पतालों के दस्तावेजों और व्यवस्थाओं का विस्तृत सत्यापन कराया गया। जांच के दौरान अस्पतालों से फायर एनओसी, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सहित मरीजों की सुरक्षा और अस्पताल संचालन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज मांगे गए।उन्होंने बताया कि मार्च से ही अस्पतालों को निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिए लगातार अवसर दिए गए और आवश्यक सूचनाएं भी उपलब्ध कराई गईं। इसके बावजूद निर्धारित समयसीमा में जरूरी शर्तें पूरी नहीं करने वाले अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सत्यापन के दौरान कई अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मानकों में कमियां पाई गईं। इनमें फायर एनओसी जैसे आवश्यक सुरक्षा मानकों का पूरा न होना भी शामिल है।ब्रजेश पाठक ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों को बेहतर और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।

सात प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले, ज्योति राय समेत कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारी

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में फेरबदल करते हुए सात अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसमें अपर जिलाधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट और उपजिलाधिकारी स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। तबादलों के तहत ज्योति राय को अपर आयुक्त आजमगढ़ मंडल, जबकि संदीप केला को अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) बलरामपुर बनाया गया है।जारी सूची के अनुसार ज्योति राय वर्तमान में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) बलरामपुर के पद पर तैनात थीं। उन्हें अब अपर आयुक्त आजमगढ़ मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। नगर मजिस्ट्रेट बांदा संदीप केला का तबादला कर उन्हें अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) बलरामपुर बनाया गया है उपजिलाधिकारी बुलंदशहर दिनेश चंद्र को नगर मजिस्ट्रेट बांदा के पद पर तैनाती दी गई है। वहीं उपजिलाधिकारी चंदौली श्रीमती दया ओझा को अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) बरेली की जिम्मेदारी सौंपी गई है।नगर मजिस्ट्रेट प्रयागराज विनय कुमार सिंह का तबादला कर उन्हें नगर मजिस्ट्रेट गोरखपुर बनाया गया है। वहीं नगर मजिस्ट्रेट गोरखपुर उत्कर्ष श्रीवास्तव को नगर मजिस्ट्रेट प्रयागराज के पद पर भेजा गया है। इसके अलावा जन भवन में कंट्रोलर के पद पर तैनात श्रीमती निधि पांडेय को उपजिलाधिकारी लखनऊ के पद पर नई तैनाती दी गई है।शासन की ओर से सभी अधिकारियों को नई तैनाती वाले पदों पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

संविदा कर्मचारियों के धरना-प्रदर्शन से पहले पावर कॉरपोरेशन सतर्क

लखनऊ। विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ उत्तर प्रदेश की ओर से आज प्रदेश के सभी जिलों में प्रस्तावित सत्याग्रह और धरना-प्रदर्शन को देखते हुए उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सभी विद्युत वितरण निगमों और केस्को को बिजली आपूर्ति हर स्थिति में सामान्य बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। कॉरपोरेशन ने विद्युत केंद्रों, संयंत्रों और अपनी संपत्तियों के साथ कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा आवश्यकता पड़ने पर जिला और पुलिस प्रशासन से सहयोग लेने को कहा है।पावर कॉरपोरेशन के निदेशक (कार्मिक, प्रशासन एवं औद्योगिक संबंध) डॉ. जॉन मथाई की ओर से 10 अगस्त को जारी पत्र में पूर्वांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल और मध्यांचल विद्युत वितरण निगमों के प्रबंध निदेशकों तथा केस्को को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। पत्र में कहा गया है कि विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ ने विभिन्न मांगों को लेकर 13 अगस्त को प्रदेश के सभी जनपदों में सत्याग्रह और धरना-प्रदर्शन करने का नोटिस दिया है।कॉरपोरेशन ने शासन के 27 मई 2026 के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न निगमों में उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत छह माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया गया है।

गोमती को सीवेज प्रदूषण से मुक्त करने की तैयारी तेज, 45 नालों की हुई पहचान

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। राजधानी में गोमती नदी को सीवेज प्रदूषण से मुक्त करने के लिए योगी सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। शहर से निकलने वाले सीवेज को सीधे गोमती में पहुंचने से रोकने के लिए नालों की टैपिंग, सीवेज का प्रवाह मोड़ने, मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की क्षमता बढ़ाने और नए एसटीपी स्थापित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। ड्रोन सर्वे में गोमती में गिरने वाले 45 नालों की पहचान हुई है। इनमें से 12 नालों से करीब 75 एमएलडी सीवेज की टैपिंग की जा चुकी है, जबकि शेष 28 अनटैप्ड और आंशिक रूप से टैप्ड नालों से करीब 260 एमएलडी सीवेज नदी में पहुंच रहा है।वर्ष 2026 में लखनऊ नगर की अनुमानित आबादी करीब 45.56 लाख है। शहर में 110 वार्ड और लगभग 7.52 लाख घर हैं, जिनमें करीब 4.01 लाख यानी 53.32 प्रतिशत घर ही सीवरेज नेटवर्क से जुड़े हैं। आबादी के हिसाब से शहर में करीब 546.77 एमएलडी घरेलू सीवेज उत्पन्न होता है, जबकि वास्तविक डिस्चार्ज करीब 880.70 एमएलडी है। इसमें 690.33 एमएलडी सीवेज नालों और 190.71 एमएलडी सीवर नेटवर्क के माध्यम से प्रवाहित होता है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अधिशासी निदेशक जोगिंदर सिंह ने बताया कि नदियों को स्वच्छ बनाना सरकार की प्राथमिकता है। गोमती में गिरने वाले नए नालों की पहचान की गई है और उन्हें जल्द शोधित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

बीबीएयू में प्रोटोटाइप विकास और सत्यापन पर द्विदिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल के संरक्षण में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल की ओर से 'प्रोटोटाइप डेवलपमेंट एंड वेलिडेशन क्लीनिक' विषय पर आयोजित द्विदिवसीय कार्यशाला का गुरुवार को शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने की। इस अवसर पर इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल के अध्यक्ष प्रो. नवीन कुमार अरोड़ा, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ के साइंटिस्ट जी डॉ. पंकज कुमार श्रीवास्तव, प्रो. बाल चंद्र यादव, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल के निदेशक प्रो. शिशिर कुमार और कार्यक्रम संयोजक डॉ. जीवन सिंह मौजूद रहे।कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। आयोजन समिति की ओर से अतिथियों का पौधा भेंट कर स्वागत किया गया। प्रो. बाल चंद्र यादव ने उपस्थित अतिथियों, शिक्षकों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों का स्वागत किया, जबकि कार्यक्रम संयोजक डॉ. जीवन सिंह ने कार्यशाला के उद्देश्य और रूपरेखा की जानकारी दी।कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने कहा कि देश के बजट निर्माण में सरकार शोध एवं विकास के क्षेत्र को विशेष महत्व दे रही है और अनुसंधान एवं विकास से जुड़े क्षेत्रों में निवेश तथा बजट में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि शोध के क्षेत्र में वित्तीय सहयोग का बड़ा हिस्सा अभी भी सार्वजनिक क्षेत्र से प्राप्त होता है। ऐसे में शोध एवं नवाचार को समाज और उद्योग की जरूरतों से जोड़ने के लिए और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।उन्होंने कहा कि भारत सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बड़े उपभोक्ता के रूप में उभरा है, लेकिन अब देश को केवल उपभोक्ता बने रहने के बजाय उत्पादक बनने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। इसके लिए ऐसे नए उत्पादों और तकनीकों का विकास जरूरी है, जो वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने के साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर सकें। उन्होंने शोधकर्ताओं से अपने शोध को व्यावहारिक समाधान में बदलने का आह्वान करते हुए कहा कि शोध का उद्देश्य केवल नया ज्ञान पैदा करना नहीं, बल्कि समाज और देश की वास्तविक समस्याओं का समाधान करना भी होना चाहिए।

इकाना क्रिकेट मैच को लेकर लखनऊ में यातायात डायवर्जन, 14 अगस्त को शहीद पथ पर कई मार्गों पर प्रतिबंध

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। इकाना क्रिकेट स्टेडियम में 14 अगस्त को होने वाले क्रिकेट मैच को देखते हुए लखनऊ यातायात पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए व्यापक डायवर्जन योजना जारी की है। मैच के दौरान शहीद पथ और उससे जुड़े प्रमुख मार्गों पर वाहनों का दबाव बढ़ने की संभावना को देखते हुए कई स्थानों पर सामान्य यातायात को वैकल्पिक मार्गों से गुजारा जाएगा। यह व्यवस्था मैच समाप्त होने और यातायात सामान्य होने तक प्रभावी रहेगी।यातायात पुलिस के अनुसार कमता शहीद पथ तिराहा, अयोध्या रोड से आने वाला सामान्य यातायात शहीद पथ के रास्ते सुल्तानपुर रोड, रायबरेली रोड और कानपुर रोड की ओर नहीं जा सकेगा। ऐसे वाहनों को कमता तिराहा, इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान, समतामूलक चौराहा, लालबत्ती चौराहा, करियप्पा चौराहा, तेलीबाग, बाराबिरवा अथवा इन्दिरा नहर चौराहा होते हुए किसान पथ से गंतव्य की ओर भेजा जाएगा। इसी तरह शहीद पथ कानपुर रोड तिराहे से सुल्तानपुर, रायबरेली और अयोध्या रोड की ओर जाने वाले वाहनों को भी वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा।गोसाईंगंज कस्बा तिराहा और अमूल डेयरी कटिंग से अहिमामऊ की ओर जाने वाले बड़े वाहन, बस और वाणिज्यिक वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। इन्हें वृंदावन योजना अथवा कबीरपुर किसान पथ से वैकल्पिक मार्ग दिया जाएगा। उतरेठिया अंडरपास से शहीद पथ होकर अहिमामऊ और कमता की ओर जाने वाले बड़े वाहन, बस और वाणिज्यिक वाहन तेलीबाग, बाराबिरवा, करियप्पा चौराहा अथवा हरीकंशगढ़ी किसान पथ होकर अपने गंतव्य तक जा सकेंगे।हुसड़िया अंडरपास की ओर से अहिमामऊ और शहीद पथ कानपुर रोड तिराहे की ओर सामान्य यातायात प्रतिबंधित रहेगा। इन वाहनों को शहर क्षेत्र से होते हुए 1090 चौराहा के रास्ते भेजा जाएगा। लालबत्ती चौराहा से अहिमामऊ, सुल्तानपुर, रायबरेली और कानपुर रोड की ओर जाने वाले बड़े वाहन, बस और वाणिज्यिक वाहन करियप्पा चौराहा, तेलीबाग अथवा बंगलाबाजार और बाराबिरवा चौराहा होते हुए आगे जा सकेंगे।सुल्तानपुर रोड की ओर से आने वाले सामान्य वाहनों का अमूल तिराहा से अहिमामऊ चौराहा की ओर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इन वाहनों को अमूल तिराहा से डायवर्ट कर लूलू मॉल कटिंग से शहीद पथ पर भेजा जाएगा। वहीं सुल्तानपुर रोड से पुलिस मुख्यालय की ओर जाने वाले वाहनों को एचसीएल तिराहा से प्लासियो तिराहा होते हुए जाने की अनुमति नहीं होगी।

नगराम पुलिस ने 78 किलो गांजे के साथ दो तस्करों को दबोचा, 16 लाख का माल बरामद

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। नगराम पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरजनपदीय गांजा तस्करी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से छह बोरियों में रखा कुल 78.330 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 16 लाख रुपये बताई गई है। तस्करी में इस्तेमाल ईको स्पोर्ट कार, 12,500 रुपये नकद और करीब 2.30 लाख रुपये कीमत के दो आईफोन भी बरामद हुए हैं।पुलिस के मुताबिक 13 अगस्त को नगराम पुलिस नगराम-गंगागंज मार्ग स्थित हुसैनाबाद तिराहे पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने काले रंग की ईको स्पोर्ट कार को रोककर तलाशी ली। वाहन में सवार प्रिंस जायसवाल पुत्र रामप्रकाश जायसवाल, निवासी ग्राम समेसी, थाना नगराम और अभिजीत पटेल उर्फ सेना पुत्र काशीप्रसाद, निवासी भाटन टोला, कस्बा व थाना नगराम को हिरासत में लिया गया। वाहन की तलाशी में छह बोरियों से 78.330 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ।पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनका गिरोह बहराइच से गांजा लाकर लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी और आसपास के जिलों में सप्लाई करता था। गिरोह के अन्य सदस्य अलग-अलग क्षेत्रों में गांजे की खपत और बिक्री करते थे। आरोपियों ने बताया कि इस अवैध कारोबार से होने वाले मुनाफे को आपस में बांटकर खर्च किया जाता था। पुलिस के अनुसार गांजा तस्करी से अर्जित रकम से ही दोनों ने महंगे आईफोन भी खरीदे थे।

हमर छत्तीसगढ़ के पहिली लोक परबः हरेली तिहार

छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कहे जाथे। इहाँ के माटी, खेती-किसानी, लोक परंपरा अउ संस्कृति के बीच में एक-दूसर ले गहरा जुड़ाय हवय। एही समृद्ध लोक संस्कृति के पहिली अउ सबले महत्तम परब आय - हरेली तिहार। सावन अमावस के दिन मनाय जाथे, ये तिहार सब पूजा-पाठ के अवसर नहीं हे, बल्कि हरियर प्रकृति, किसान, खेती, पशुधन अउ लोक जीवन के सम्मान के परब आय।

हरेली शब्द के मतलबे आय - हरियाली। जब सावन के बरखा ले धरती हरियर चुनरी ओढ़ लेथे, खेत मं धान के पौधा लहलहाय लगथे, किसान के मन मा नई आस जगथे, त पूरा छत्तीसगढ़ हरेली तिहार के रंग मं रंग जाथे। इही कारण से हरेली ला छत्तीसगढ़ के पहिली लोक परब कहे जाथे।

हरेली के दिन किसान अपन हल, नागर, रापा, कुदारी, फावड़ा, हंसिया, गाड़ी-बैला जइसने खेती के सब्बो औजार मन के साफ-सफाई करके पूजा करथें। ये औजार के पूजा नहीं हे, बल्कि किसान के मेहनत, पसीना अउ अन्नदाता के सम्मान के प्रतीक आय। खेती मा सहयोग करे वाला गाय-बैला मन के घलो पूजा करके ओकर सेवा अउ महत्व ला याद करे जाथे।

ए दिन घर के दुवारी मा नीम, भिलवा अउ दूसर औषधीय डारी लगाय जाथे। लोक मान्यता हवय कि एखर ले नकारात्मक शक्ति दूर रहिथे अउ घर-परिवार सुरक्षित रहिथे। गांव-गांव मा बैइगा, गुनिया अउ पारंपरिक वैद्य पूजा-पाठ करथें। किसान मन बढ़िया बरसा, भरपूर फसल, पशुधन के सुख-समृद्धि अउ परिवार के खुशहाली बर भगवान ले प्रार्थना करथें।

हरेली के दिन गांव-देहात में घरो-घर गुड़-चीला, फरा के संग गुलगुला भजिया, चौसेला, औउ बोबरा घलो बनाए जाथे, जेखर ले हरेली तिहार के उमंग हा अउ बाढ़ जाथे। किसान मन अपन किसानी औजार के पूजा-पाठ कर गाय-बैला ला दवई खवाये जाथे, ताकि वो हा सालभर बने रहाय। गांव-देहात के संगे-संग शहर मन डाहर घलो हरेली तिहार मनाये जाथे। ऐसे माने जाथे कि हरेली तिहार बर खेती-किसानी के पहली काम हा पूरा हो जथे। यानी बोआई, बियासी के बाद किसान औउ गरवा मन आराम करथे। ये दिन गाय-गरवा मन ला बीमारी ले बचाय बर बगरंडा और नमक खवाय जाथे औउ आटा मा दसमूल-बागगोंदली ला मिलाके घलो खवाथे। गांव मा लोकगीत, नाचा-गम्मत, मांदर के थाप अउ पारंपरिक व्यंजन ले पूरा माहौल आनंदमय हो जाथे।

हरेली के सबले बड़े आकर्षण मा एक आए गेड़ी चढ़ना। बांस के बने गेड़ी मा चढ़के लइका मन गांव भर घूमथें, दौड़ लगाथें अउ लोक खेल के आनंद लेथें। ऐहा गेड़ी खेल नइ हे, बल्कि छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति, संतुलन अउ उत्साह के पहचान आय।

आज के आधुनिक समय मा जिहां कई लोक परंपरा धीरे-धीरे कम होवत जात हे, ओतकेच हरेली तिहार हमन ला अपन जड़, अपन माटी अउ अपन संस्कृति ले जुड़े रेहे के सीख देथे। ये परब बताथे कि प्रकृति के बिना जीवन अधूरा हवय अउ खेती-किसानी हमर असली पहचान आय।

छत्तीसगढ़ शासन घलो हरेली तिहार ला राज्य के सांस्कृतिक पहचान के रूप मा बढ़ावा देवत हवय। गांव-गांव मा हरेली तिहार मा गेड़ी दौड़, वृक्षारोपण, कृषि औजार पूजा, लोकनृत्य अउ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करे जाथें। एखर ले नई पीढ़ी अपन लोक संस्कृति अउ परंपरा ला जाने-समझे के मौका पाथे।

आज जब पर्यावरण संरक्षण पूरा दुनिया बर चुनौती बन गे हवय, त हरेली तिहार के महत्व अउ बढ़ गे हवय। ये परब हमन ला रूख लगाय, हरियाली बचाय, पानी के संरक्षण करे अउ प्रकृति संग संतुलन मा जीए के प्रेरणा देथे।

हरेली एक तिहार नइ, बल्कि छत्तीसगढ़िया अस्मिता, किसान के सम्मान, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता अउ लोक संस्कृति के गौरव के प्रतीक आय। ये परब हमन ला सिखाथे कि जेन धरती हमन ला अन्न देथे, जेन किसान मेहनत करथे अउ जेन प्रकृति हमन ला जीवन देथे, ओकर सम्मान करना हमर सबले बड़े जिम्मेदारी आए।

आवव, हरेली तिहार के पावन अवसर मा हम सब्बो हरियर छत्तीसगढ़, स्वच्छ पर्यावरण अउ अपन समृद्ध लोक संस्कृति के संरक्षण के संकल्प लेवव। इही हरेली के असली संदेश अउ हमर छत्तीसगढ़ के गौरव आए। जय छत्तीसगढ़।

असामाजिक हो रहे सोशल मीडिया का नियमन जरूरी

सोशल मीडिया को लोकतंत्र के बड़े मंच के रूप में 17 दिसंबर 2010 को ट्यूनिशिया के सिटी बौजिज शहर में फलों का ठेला लगाने वाले मोहम्मद बोआजीजी की आत्महत्या के बाद हुए उबाल के बाद देखा जाने लगा।

उमेश चतुर्वेदी

दिल्ली में बीस जुलाई को काकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा और 23 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी के जेन जी के संबोधन की वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम से हटाए जाने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत चर्चा में हैं। चर्चा से ज्यादा उनकी भूमिका कहीं ज्यादा विमर्श के केंद्र में है। इसमें दो राय नहीं कि दुनियाभर में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्यादा प्रचलन में हैं, उनमें से ज्यादातर विदेशी हैं। जाहिर है कि वे उन जगहों के कानूनों और सांस्कृतिक परंपराओं से ज्यादा संचालित हैं, जहां उनके मुख्यालय हैं। इसलिए अपने व्यापक हितों के लिए वे अपने प्रचलन वाले देशों की परंपराओं और संस्कृतियों को सवालों के घेरे में लाने, उसका उपहास उड़ाने और उन्हें तार-तार करने वाला अलगोरिदम उन्होंने विकसित कर रखा है। जिसका खामियाजा तीसरी दुनिया के देश और वहां की सांस्कृतिक परंपराएं उठा रही हैं।

सोशल मीडिया को लोकतंत्र के बड़े मंच के रूप में 17 दिसंबर 2010 को ट्यूनिशिया के सिटी बौजिज शहर में फलों का ठेला लगाने वाले मोहम्मद बोआजीजी की आत्महत्या के बाद हुए उबाल के बाद देखा जाने लगा। म्यूनिसिपल कर्मचारियों की सख्ती के चलते क्षुब्ध बोआजीजी ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। किसी ने इस घटना को सोशल मीडिया पर डाल दिया। सोशल मीडिया के तत्कालीन अलगोरिदम ने इस घटना को इस रूप में प्रस्तुत किया कि समूचे अरब जगत में उबाल आ गया। नागरिक अधिकारों की स्थापना और लोकतंत्र की बहाली की मांग को लेकर अरब देशों की जनता सड़कों पर उतर आई। इसका ही नतीजा मिस्र की राजधानी काहिरा के तहरीर चौक पर दिखा। जहां महीनों तक लोग जमे रहे और वहां के राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा। यह आग सीरिया, यमन और लीबिया तक जा पहुंची। वहां के पारंपरिक शासकों के खिलाफ लोगों का दबा हुआ गुस्सा निकला और कई जगह सत्ताएं बदल गईं। भारत में भी इसके ही कुछ महीनों बाद अन्ना हजारे को आगे रखकर एक आंदोलन छेड़ा गया। जिसकी परिणति आम आदमी पार्टी के रूप में हुई और वह दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई। फिर पंजाब में भी उसने पैठ बना ली।

इन घटनाओं को याद करना इसलिए जरूरी है कि इन सबके पीछे सोशल मीडिया के जरिए त्वरित गति से फैलाई गई सूचनाओं का हाथ सबसे ज्यादा रहा। तब सोशल मीडिया को लोकतंत्र के लिए जरूरी बताया गया। सोशल मीडिया के बारे में कहा गया कि लोकतंत्र में सबकी आवाज पहुंचाने और उन्हें मौका देने का यह बड़ा माध्यम है। इसे लोकतंत्र के वाजिब और जरूरी औजार के रूप में भी मान्यता मिली। लेकिन बीतते वक्त के साथ पता चल रहा है कि जिसे हम सोशल मीडिया कहते हैं, वह लोकतंत्र के लिए जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा अनसोशल यानी असामाजिक भी है। यह ठीक है कि सोशल मीडिया के जरिए व्यवस्था की अंधी सुरंग में खो रही आवाजों को मौका मिलता है। लेकिन यह उतना ही सच है कि इस माध्यम ने लोगों की नजर का पानी उतार दिया है। लोग अब लिहाज करना भूल गए हैं। सोशल मीडिया पर अगर किसी की बात पसंद नहीं आती तो उसे खुलेआम गालियां दी जा सकती हैं। उसके चरित्र पर आक्षेप लगाया जा सकता है। उसका चरित्र हनन किया जा सकता है। चाहे वह व्यक्ति सामाजिक जीवन में कितना ही प्रतिष्ठित क्यों न हो, उसकी उम्र चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो।

सोशल मीडिया मंचों ने अपना अलगोरिदम भी ऐसा विकसित किया है, जो अच्छी बातों, सामाजिक चिंतन और बेहतर कल की बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देखा। एक तरह से कहें तो वह इसकी अनदेखी ही करता है। लेकिन जैसे ही किसी को कोई गाली देता है, किसी के चरित्र का बेवजह ही हनन करता है, किसी का घटिया कार्टून बनाता है, सोशल मीडिया का अलगोरिदम उसे फैलाने में द्रुत गति से जुट जाता है। सोशल मीडिया ने अब तक पर्दे के पीछे रही नंगई को भी उजागर कर दिया है। आज रील्स के चक्कर में अधनंगे और कई बार करीब-करीब नग्न फोटोग्राफ और वीडियो तक जारी किए जा रहे हैं। भले ही अपने परिवारों में महिलाएँ और युवतियां सलीके से रहती हों, लेकिन सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि पाने और उसके जरिए कुछ कमाने के चक्कर में अपने शील और अपनी लज्जा को भी बेपर्दा कर रही हैं। सोशल मीडिया कितना असमाजिक हो चुका है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसका अलगोरिदम अश्लीलता को बढ़ावा देता है, लेकिन शील और लज्जा की बात को अपने मंच के किसी कोने में डाल देता है। कह सकते हैं कि वर्चुअल स्पेस के किसी अंधेरे कोने में उसे गुम कर देता है।

तीन साल पहले प्यू रिसर्च सेंटर ने 19 विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में सोशल मीडिया को लेकर एक शोध किया था। उसके मुताबिक, आम नागरिकों की नजर में सोशल मीडिया राजनीतिक जीवन के लिए रचनात्मक और विनाशकारी दोनों है। इस अध्ययन में शामिल देशों में, औसतन 57 प्रतिशत लोगों ने माना कि सोशल मीडिया लोकतंत्र के लिए अच्छा है, लेकिन इसे बिनाशकारी मानने वालों की संख्या भी कम नहीं रही। करीब 35 प्रतिशत से ज्यादा लोगों का का कहना था कि सोशल मीडिया विनाशकारी साबित हो रहा है। सिर्फ 34 प्रतिशत अमेरिकियों ने ही सोशल मीडिया को लोकतंत्र के लिए लाभकारी माना, जबकि 64 फीसद का कहना था कि इसने नकारात्मक प्रभाव ज्यादा डाला है। हाल ही में जेन जी से चर्चा के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी सोशल मीडिया को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। उसमें उन्होंने कहा है कि यदि सोशल मीडिया पर उनके कारण दस लाख लोग कोई गलत निर्णय लेते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी भी है। सोशल मीडिया पर सकारात्मक, उपयोगी और समाजहित की सामग्री साझा करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर केवल प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करना चाहिए। जेन-ज़ी में भी यह विवेक विकसित होना चाहिए कि क्या सही है और क्या नहीं। वरिष्ठ पीढ़ी की भी जिम्मेदारी है कि वह नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करे तथा उन्हें सही और गलत के बीच अंतर समझाए। सोशल मीडिया का अनसोशल चेहरा और मंच आर्थिक कमाई का जरिया भी है। नंगई, हिंसा और व्यभिचार-अतिचार की कहानियां, दृश्य, वीडियो और फोटो को वायरल करने में उसका कोई सानी नहीं है। इस बहाने इसे प्रसारित करने वाले को सोशल मीडिया मंच आर्थिक कमाई भी कराते हैं। और तो और, वे खुद भी ऐसी घटनाओं, दृश्यों को प्रसारित-प्रचारित और वायरल करने के लिए बड़ी रकम लेते हैं। संसदीय समिति के सामने फेसबुक और इंस्टाग्राम की संचालक कंपनी मेटा के अधिकारियों ने माना है कि काकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान गाली, हिंसा आदि को बढ़ावा देने के लिए पैसे भी लिए थे। इन कोशिशों का मकसद भारत में व्यापक पैमाने पर लोगों को उत्तेजित करके अराजकता फैलाना था। इस लिहाज से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म राष्ट्रों के अंदरूनी मामलों में लोकतंत्र की रक्षा के मुखौटे के पीछे से दखल भी दे रहे हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती भी दे रहे हैं।

व्यंग्य

छात्रों की मांग

झारखंड सरकार को छात्रों के प्रति संवेदनशील रुख अपनाना चाहिए। कांग्रेस जैसे उसके सहयोगी दलों पर भी ये जिम्मेदारी है कि वे अलग मिसाल पेश करें, ताकि विपक्ष-पक्ष का फर्क (अगर है, तो) जाहिर हो सके।

'कॉकरोच' आंदोलन से केंद्र में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां खड़ी हुईं, जिसमें विपक्षी दलों ने अपना फायदा देखा हो, तो वह लाजिमी ही है। लेकिन इन दलों को यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि युवा आक्रोश राजनीतिक दायरे में बंधा हुआ नहीं है। इसकी जड़ें बढ़ती गई अवसरहीनता, जवाबदेही का अभाव और शासकीय असंवेदनशीलता से बने दमघोंटू माहौल में छिपी हैं। इसलिए जिन राज्यों में गैर-भाजपा सरकारें हैं, और वहां ऐसे मुद्दे उठते हैं, तो वहां की सरकारों को उत्तरदायी और सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाना चाहिए। मगर झारखंड के छात्र- नौजवानों की शिकायत है कि हेमंत सोरेन उनकी मांगों के प्रति असहनशील बनी हुई है। रांची में 29 जुलाई से सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है।

महीने भर पहले झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा का रिज़ल्ट आने के बाद से यह विवाद शुरू हुआ। इस परीक्षा में गड़बड़ियों का आरोप है। साथ ही झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा-2025 की प्रारंभिक परीक्षा में भी धांधली के आरोप लगे हैं। जेपीएससी परीक्षा कांड में कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन छात्रों की मांग है कि ये परीक्षा रद्द की जानी चाहिए। छात्र संगठनों ने परीक्षा धांधली की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग भी की है। इसके अलावा वो तमाम शिकायतें भी उभर कर सामने आई हैं, जिनकी चर्चा 'कॉकरोच' आंदोलन के दौरान हुई।

मसलन, छात्रों की शिकायत है कि झारखंड में भर्ती परीक्षाएं नियमित रूप से नहीं होतीं। कई बार परीक्षाओं को पिछले साल की भर्ती से जोड़ दिया जाता है, जिसका असर उम्मीदवारों की उम्र सीमा पर असर पड़ता है। भाजपा शासित राज्यों में ऐसी शिकायतों के प्रति बेरहम रुख देखने को मिला है। वैसा ही नजरिया गैर-भाजपा सरकारें भी अपनाती हैं, तो युवा आक्रोश के केंद्र में पूरा राजनीतिक तबका आ सकता है। इसलिए झारखंड सरकार को छात्रों के प्रति अधिक संवेदनशील नजरिया अपनाना चाहिए। कांग्रेस जैसे उसके सहयोगी दलों पर भी ये जिम्मेदारी है कि वे झारखंड में अलग मिसाल कायम करें, ताकि विपक्ष और पक्ष का फर्क (अगर है, तो) जाहिर हो सके।

ब्लॉग

एक न्यायाधिकरण, जो अपने आप में पूर्ण है

एन. वेंकटरमण

हमारे सार्वजनिक अधिनियमों में न्यायाधिकरणों के गठन से जुड़े कुछ ही प्रश्न ऐसे हैं, जिनकी इतनी बार पुनर्समीक्षा हुई है। 1987 के एस. पी. संपत कुमार मामले से लेकर नवंबर 2025 में मद्रास बार एसोसिएशन से संबंधित निर्णय तक, न्यायालयों ने कानून निरस्त किये, निर्देश जारी किए और फिर उसी आधार पर स्वयं को नए कानूनों की समीक्षा करते हुए पाया। यह विषय इतने चक्र से गुजरा है, जो अपने आप में दर्शाता है कि समस्या कितनी कठिन रही है। न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, 2026 इसीलिए ध्यान आकर्षित करता है क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अंततः वास्तविक समस्या की पहचान कर ली है और उम्मीद है कि समाधान भी खोज लिया है।

दूसरे देशों और स्वयं के अनुभव से मिली सी

यह समस्या केवल भारत तक सीमित नहीं है। दूसरे देशों को भी इसका सामना करना पड़ा है और उनका निदान ध्यान देने योग्य है। ब्रिटेन में जब सर एंड्रयू लेगट ने 2001 में इस क्षेत्र की समीक्षा की, तो पाया कि सत्तर से अधिक न्यायाधिकरणों का प्रशासन उन्हीं विभागों द्वारा किया जा रहा था, जिनके निर्णयों की वे समीक्षा करते थे। उन्होंने इसे मूल दोष माना। उनका उपाय कार्यकाल में बदलाव या योग्यताओं को परिष्कृत करना नहीं था। उनका समाधान था कि न्यायाधिकरणों को उनके प्रायोजक विभागों से अलग कर उनका प्रशासन एकल सेवा के अधीन किया जाए। यही सुधार 2007 के अधिनियम का आधार बना। यह सुधार संरचनात्मक था। उसने निर्भरता के लक्षणों को नहीं, बल्कि निर्भरता की वजह का समाधान किया।

भारत ने न्यायाधिकरणों की व्यवस्था को प्रारंभिक चरण में ही अपनाया और, कुल मिलाकर, यह सफल रही। 1941 में स्थापित आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण आज भी विशेषज्ञतापूर्ण न्यायनिर्णयन के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। इस प्रारूप को अनुच्छेद 323ए और 323बी तथा प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 द्वारा आगे बढ़ाया गया और बाद में विभिन्न नियामक क्षेत्रों में उस उच्च स्तर पर इसका विस्तार हुआ, जिसे उच्च न्यायालय नहीं ले सकते थे। पर हमारी समस्या अलग तरह की थी। जैसा कि न्यायालय की 2020 की टिप्पणी में कहा गया कि स्वतंत्रता तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब न्यायाधिकरणों को अपने कार्य करने के लिए कार्यपालिका के कंधों का सहारा न लेना पड़े।

इस बारे में सुधार एक से अधिक बार किए गए हैं और हर बार सच्ची भावना के साथ किए गए हैं। इसके बाद होने वाली अधिकांश मुकदमेबाजी इस बात को लेकर रही कि कार्यकाल तीन वर्ष का होना चाहिए या चार या पांच वर्ष का, न्यूनतम आयु पचास वर्ष होना स्वीकार्य है या नहीं, और एक नाम या दो नामों की समिति की सिफारिश होनी चाहिए। सम्मानपूर्वक कहना होगा कि इनमें से कोई भी बात मूल समस्या तक नहीं पहुंचती। स्वतंत्र न्यायाधिकरण अंकगणित पर निर्भर नहीं करते। कार्यकाल, आयु और नामों की संख्या वे लक्षण हैं जिनके माध्यम से रोग का निदान किया गया है। वे स्वयं बीमारी नहीं हैं।

मूल बात यह है कि न्यायाधिकरण एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर संस्था होनी चाहिए। उसका अपना प्रतिष्ठान होना चाहिए, अपने सदस्यों के चयन का उसका अपना साधन होना चाहिए, उन पर निगरानी रखने और उन्हें अनुशासित करने की अपनी व्यवस्था होनी चाहिए तथा परिसर, कर्मचारियों और धन की अपनी व्यवस्था होनी चाहिए। जहां ये सभी व्यवस्थाएं मौजूद हों, वहां स्वतंत्रता स्वाभाविक रूप से आ जाती हैं।

नया विधेयक उन सभी बिंदुओं पर न्यायालय को उत्तर देता है, जिन पर न्यायालय अपनी बात कह चुका है। लेकिन इससे भी बढ़कर एक ऐसी संस्था स्थापित करने का प्रयास है जो उन उत्तरों को स्वयं लागू करने योग्य बना दे। राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना कानून द्वारा की जानी है। उसका अस्तित्व, गठन और कार्य किसी कार्यपालिका आदेश से नहीं, बल्कि अधिनियम से संचालित होंगे और उसे चयन, निगरानी, अनुशासन तथा न्यायाधिकरणों की आवश्यकताओं के आकलन का दायित्व है। उसके चारों ओर एक स्थायी पेशेवर सचिवालय स्थापित किया जाएगा।

विधेयक में उन प्रत्येक बिंदुओं पर न्यायिक सर्वोच्चता बनाए रखी गयी है, जहां उसका महत्व है। आयोग की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाएगी और उसमें न्यायिक बहुमत का प्रावधान है। समितियों की अध्यक्षता न्यायिक रूप से की जाती है तथा निर्णायक मत न्यायिक अध्यक्ष के पास ही होता है। चयन, निगरानी, अनुशासन और कार्य-प्रदर्शन— सभी का नेतृत्व न्यायिक तौर पर किया जाता है।

यह उस बात के अनुरूप है जो न्यायालय आर. गांधी मामले के बाद से कहता आया है कि कार्यपालिका, जो सबसे बड़ी वादी है, उन लोगों के चयन में प्रमुख भूमिका नहीं निभा सकती जो उसके मामलों का निर्णय करते हैं।

इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण यह है कि सर्वोच्चता का अर्थ नियंत्रण नहीं है। पूरी व्यवस्था न्यायिक पक्ष को सौंप देना भी चुनौतियों के रूप में देखा जाता है। इसलिए यह विधेयक न्यायाधिकरण को तीन स्तरों से कार्यपालिका और न्यायपालिका से समान दूरी पर रखता है। केंद्र सरकार नियमों द्वारा व्यापक सिद्धांत निर्धारित करती है। आयोग उन नियमों को लागू करने के तरीके को नियंत्रित करने वाले विनियम बनाता है। सचिवालय इसी ढांचे के तहत काम करता है। उसे कार्य करने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन दिया गया है, लेकिन परिचालन स्तर पर उसे निर्देशित नहीं किया जाता और वह अपने कार्य अधिनियम से प्राप्त करता है, न कि अधिकार या कार्य किसी दूसरे को सौंपे जाने के प्रत्यायोजन से।

इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग, सचिवालय और कार्यपालिका के संयोजन से उत्पन्न नियंत्रण और संतुलन की वास्तविक व्यवस्था है। सचिवालय पात्रता की जांच और उसका अभिलेखन तैयार करेगा, जिसके आधार पर प्रत्येक निर्णय लिया जाना है। वह प्रकाशित विनियमों से बंधा है और अपने कार्यों का रिकॉर्ड रखेगा।

विधेयक द्वारा कायम यही वह नाजुक संतुलन है। इसमें न तो प्रशासन में न्यायिक हस्तक्षेप है और न ही वास्तविक रूप से कार्यपालिका पर निर्भरता, जबकि चयन, निगरानी, अनुशासन और कार्य-प्रदर्शन में न्यायिक सर्वोच्चता बनी रहती है। कनाडा ने 2014 में इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया था, जब उसने अपने संघीय न्यायाधिकरणों की सहायक सेवाओं को एक ही संगठन के अधीन लाते हुए उनके न्यायनिर्णयन संबंधी स्वतंत्रता बरकरार रखी।

इस प्रकार के कानून का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं किया जाना चाहिए कि वह न्यायिक चुनौती में टिकता है या नहीं। इसका मूल्यांकन इस तथ्य के आधार पर होना चाहिए कि क्या वह उन स्थितियों को समाप्त करता है, जिनसे ये चुनौतियां पैदा हुईं। विधेयक इस कसौटी पर पूरी तरह खरा उतरता है। यदि यह अपने निर्धारित स्वरूप में काम करता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि न्यायाधिकरण व्यवस्था में काफी सुधार आएगा। इसमें वादी को अंततः ऐसा मंच मिलेगा जो उचित रूप से गठित, पर्याप्त रूप से व्यवस्थित होगा, जहां रिक्तियां समय पर भरी जाएंगी तथा जो अपने कार्य-प्रदर्शन के लिए जवाबदेह होगा। विकसित किया गया यह मॉडल, यदि सफल रहा तो भविष्य में अन्य प्रकार के चयन के लिए भी काफी उपयोगी होगा।

लेखक भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हैं। व्यक्त किए गए विचार उनके निजी हैं

गोरखपुर में डॉक्टर ने अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल से कूदकर दी जान, 1.40 करोड़ की ठगी से था परेशान

आर्यावर्त संवाददाता

गोरखपुर। गोरखनाथ क्षेत्र के बसंत इंक्लेव अपार्टमेंट की आठवीं मंजिल से गुरुवार सुबह पशु चिकित्सक डा. परमात्मा सिंह ने कूदकर जान दे दी। परिजन उन्हें खून से लथपथ हालत में पास के निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें जेल भेजी गई जालसाजी की आरोपित गरिमा सिंह का नाम लिखा है। डा. परमात्मा सिंह ने आठ दिन पहले एम्स थाने में गरिमा और गिरोह के विरुद्ध 1.40 करोड़ रुपये की ठगी करने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस के अनुसार, डा. परमात्मा सिंह मूल रूप से मऊ के मोहम्मदाबाद क्षेत्र के बरबोझी के रहने वाले थे और वर्तमान में गोरखनाथ के बसंत इंक्लेव के बी-213 ब्लाक में परिवार के साथ रह रहे थे। वह पेशे से पशु चिकित्सक थे और वर्तमान में महराजगंज जिले के एक ब्लाक में तैनात थे।

डा. परमात्मा सिंह ने पांच अगस्त को एम्स थाने में गरिमा और उसके गिरोह के विरुद्ध 1.40 करोड़ रुपये की ठगी का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपितों में गरिमा के अलावा उसके सेवानिवृत्त रेलकर्मी पिता और शिक्षक पति समेत अन्य लोग शामिल हैं। पुलिस इस मामले में गरिमा और उसके पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

इस गिरोह के विरुद्ध अब तक एम्स थाने में तीन और सहजनवा थाने में एक मुकदमा दर्ज है। पुलिस छह मामलों की जांच कर रही है। सीओ गोरखनाथ रवि कुमार सिंह ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब 9:40 बजे डायल 112 पर सूचना मिली कि डा. परमात्मा सिंह ने अपार्टमेंट की आठवीं मंजिल से छलांग लगा दी है। कमरे की तलाशी लेने पर सुसाइड नोट मिला है। उसमें गरिमा का नाम लिखा है। पुलिस सुसाइड नोट और ठगी के मुकदमे से जुड़े तथ्यों को भी जांच में शामिल कर रही है।

पीआरवी को मिली थी सूचना

पुलिस के मुताबिक, सुबह करीब 9 :40 बजे पीआरवी–112 के जरिये बसंत इंक्लेव, भगवती चौराहा के पास एक व्यक्ति के अपार्टमेंट से गिरने की सूचना मिली। सूचना पर उपनिरीक्षक पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। जांच में गिरने वाले व्यक्ति की पहचान डॉ. परमात्मा सिंह पुत्र पारसनाथ सिंह के रूप में हुई।

पत्नी भी हैं पशु चिकित्सक

डा. परमात्मा सिंह की पत्नी सावित्री सिंह भी पशु चिकित्सक हैं। दंपती अपने दो बच्चों, एक बेटा और एक बेटी के साथ बसंत इंक्लेव में रहते थे। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है। गोरखनाथ थाना प्रभारी के अनुसार, सुसाइड नोट, ठगी के मुकदमे और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।

बदायूं में हादसा : दो मंजिला मकान का अगला हिस्सा गिरा, मलबे में दबने से महिला की मौत, तीन पशु मरे

आर्यावर्त संवाददाता

उझानी (बरेली)। बदायूं के उझानी क्षेत्र के गांव मीहलाल नगला में बृहस्पतिवार तड़के करीब 5:00 बजे प्रताप सिंह का दो मंजिला मकान का अगला हिस्सा भरभराकर ढह गया। इस दौरान वहां मौजूद उनकी पत्नी अगरवती (55 वर्ष) और चार पशु दब गए। अगरवती बाहरी छोर पर दबी थीं, इसलिए उन्हें लोगों ने खींच लिया लेकिन तब तक उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वह पशुओं को खोलने गई थीं। हादसे में तीन पशु मर गए। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।

सूचना के बाद एसडीआरएफ (राज्य आपदा मोचन बल) की दो टीमें और नगर पालिका उझानी से जेसीबी बुला ली गई। एसडीआरएफ की टीम ने मलबा हटाया। इसके बाद ही मृत पशुओं को बाहर निकल गया। बताया गया कि इस मकान में कोई रहता नहीं था। अगला हिस्सा पहले

दरका हुआ था, लेकिन बारिश में भीगने की वजह से और कमजोर हो गया। जिससे यह गिर गया।

प्रताप सिंह के अलावा उनके छोटे भाई नन्हे के मकान का अगला हिस्सा भी इस हादसे में क्षतिग्रस्त हुआ है। मृतका के बेटे विपिन ने बताया कि उनकी मां उस वक्त पशुओं को खोलने के लिए गई थी। इसी दौरान हादसा हो गया। प्रताप सिंह इस मकान के पास में बने दूसरे मकान में परिवार के साथ रहते हैं। महिला की मौत होने से परिवार में कोहराम मचा है।

लो वोल्टेज, ओवरलोडिंग से जल्द मिलेगी मुक्ति

जौनपुर। बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही लो वोल्टेज, ओवरलोडिंग और बार-बार होने वाली ट्रिपिंग से राहत मिलेगी। शासन ने जिले में पांच ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर कुल 4.7 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।इस क्षमता वृद्धि से जलालपुर, बजरंगनगर, डोभी, सेहलमपुर और मुर्तजाबाद जैसे क्षेत्रों के पांच हजार से अधिक उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। इन इलाकों में बिजली का लोड बढ़ने के कारण ट्रांसफॉर्मरों पर लगातार ओवरलोडिंग की समस्या बनी रहती थी।विशेषकर गर्मी के मौसम में बिजली की मांग बढ़ने पर ट्रांसफॉर्मर खराब होने और ट्रिपिंग की शिकायतें बढ़ जाती थीं। आए दिन ट्रांसफॉर्मर में खराबी के कारण उपभोक्ताओं को घंटों बिजली कटौती का सामना करना पड़ता था, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती थी। बिजली विभाग ने पिछले महीने इन ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता वृद्धि का प्रस्ताव शासन को भेजा था, जिसे अब स्वीकृति मिल गई है।

मूसलाधार बारिश से सड़कें पानी में डूबी

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। कई दिनों से पड़ रही भीषण उमस और गर्मी के बीच मूसलाधार बारिश से शहर और ग्रामीण इलाकों में भारी जलजमाव हो गया। गुरूवार को पूर्वान्ह 40 मिनट तक हुई इस वर्षा के कारण सड़कें पानी में डूब गईं और कई घरों में भी पानी घुस गया। रुहट्टा कॉलोनी सहित कई निचले इलाकों में पानी भर गया। नगर पालिका परिषद के अधीन आने वाली नालियां और नाले पूरी तरह से भर जाने के कारण जल निकासी बाधित हुई। नगर पालिका द्वारा मामूली सफाई के के कारणए जलभराव की स्थिति गंभीर बनी हुई है। विद्युत विभाग और जिला प्रशासन ने बारिश से पहले बिजली के खंभों को पॉलीथीन या प्लास्टिक पाइप से ढकने के आदेश दिए थे। नगर के अनेक खंभे अभी भी खुले पड़े हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। विद्युत विभाग और जिला प्रशासन ने बारिश से पहले बिजली के खंभों को पॉलीथीन या प्लास्टिक पाइप से ढकने के आदेश दिए थे। हालांकि, नगर के कई खंभे अभी भी खुले पड़े हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है।पिछले दिनों ऐसे ही खुले खंभों के कारण तीन लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन जिला प्रशासन ने इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। जलभराव के कारण सड़कों के गड्ढे दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिससे चार पहिया और दो पहिया वाहन फंस रहे हैं और दुर्घटनाएं हो रही हैं।

महिलाएं जागरूक होगी तो देश भी जागरूक होगा

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में ''महिलाओं के कानूनी अधिकार, महिला सशक्तीकरण, महिला एवं बाल संरक्षण, राष्ट्रीय लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत, केन्द्रध्राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के विषयों पर सुशील कुमार सिंह, सिविल जज की अध्यक्षता ''तहसील सभागार मड़ियाहू, एवं जगवन्ती गर्ल्स इण्टर कालेज जैयरामपुर रामनगर मड़ियाहू में विधिक शिविर का आयोजन किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुशील कुमार सिंह द्वारा कन्या भ्रूण हत्या एवं महिला सशक्तिकरण के बारे में कहा की महिलाएं जागरूक होगी तो देश भी जागरूक होगा उन्होंने लोगों से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता लेने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि समाज और देश की आवश्यकता अनुसार विधियो में परिवर्तन और संशोधन होता रहता है। बताया गया कि व्यक्तिगत बंदी की सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट आ जाने के बाद संबंधित न्यायालय को तत्काल बंदी के जमानत प्रक्रिया को मानवीय एवं संवैधानिक अनुक्रम में त्वरित गति से किया जाना आवश्यक है। पैनल अधिवक्ता श्री देवेन्द्र कुमार यादव के द्वारा महिलाओं और बच्चों के अधिकार के बारे में महिला सशक्तिकरण के बारे में बताया गया की प्राचीन काल में भारत में महिला और पुरुष में कोई भी विभेद नहीं था स्त्री और बालकों को विधान और संविधान में संपूर्ण सुरक्षा दी गई है किसी महिला को पुलिस सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार नहीं कर सकती 14 वर्ष से कम बालकों को खतरनाक कामों में लगाया नहीं जा सकता है समान काम के लिए महिलाएं समान वेतन पाने और मातृत्व अवकाश की हकदार हैं।

देशभक्ति के रंग में रंगा पुलिस कमिश्नरेट, तिरंगा थामकर दिया राष्ट्रीय एकता का संदेश

आर्यावर्त संवाददाता

कानपुर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश देने के लिए गुरुवार को पुलिस कमिश्नरेट कानपुर की ओर से 'हर घर तिरंगा यात्रा 2026' निकाली गई। पुलिस कमिश्नर कार्यालय से शुरू हुई यात्रा में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने हाथों में तिरंगा लेकर लोगों को देश के प्रति सम्मान और एकता का संदेश दिया।

स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आमजन में देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित करने और राष्ट्रीय एकता का संदेश देने के उद्देश्य से गुरुवार को पुलिस कमिश्नरेट कानपुर की ओर से भव्य 'हर घर तिरंगा यात्रा 2026' का आयोजन किया गया। पुलिस कमिश्नर कार्यालय से शुरू हुई इस तिरंगा यात्रा में पुलिस विभाग के आला

अधिकारियों से लेकर जवानों तक ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज थामकर देश के प्रति अपनी अटूट निष्ठा और सम्मान को प्रकट किया।

पुलिस कमिश्नर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा की शुरुआत होते ही पूरा परिसर भारत माता के जयकारों और देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। इस दौरान पुलिसकर्मी पूरे उत्साह और गर्व के साथ हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल हुए। अधिकारियों ने सड़क मार्ग से गुजरते हुए नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने-अपने घरों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनने की भावुक अपील की।

'तिरंगा करोड़ों भारतीयों के गौरव का प्रतीक'

इस मौके पर पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने कहा कि तिरंगा सिर्फ एक ध्वज नहीं, बल्कि देश की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीर जवानों के सर्वोच्च बलिदान, हमारी राष्ट्रीय अखंडता और करोड़ों भारतीयों के गौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि 'हर घर तिरंगा' अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को देशभक्ति के सूत्र में बांधना और इस राष्ट्रीय पर्व में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है।

ये अधिकारी रहे मौजूद

देशभक्ति से लबरेज इस कार्यक्रम में अपर पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) डॉ. विपिन ताडा, अपर पुलिस आयुक्त संकल्प शर्मा, पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) दिनेश त्रिपाठी, अपर पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) स्नेहा तिवारी, अपर पुलिस उपायुक्त योगेश कुमार, अपर पुलिस उपायुक्त अर्चना सिंह, आरआई पुलिस लाइन समेत भारी संख्या में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

संक्षेप

तिरंगा यात्रा में भारत माता की जय गुंजायमान

जौनपुर ।सिरकोनी विकास खण्ड मुख्यालय से गुरुवार को एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गयी ।तिरंगा यात्रा ब्लॉक मुख्यालय से टोलप्लाजा होते हुए हौज गांव तक गयी ।तिरंगा यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए ब्लॉक प्रमुख बंसराज सिंह ने कहा कि आजादी की लड़ाई में हमारे कितने अपनों ने अपने जान का बलिदान दिया ।तब जाकर हमें आजादी मिली ।हमारे शहीदों ने हमे गुलामी की जंजीरों से मुक्ति दिलाया ।विकास खण्ड अधिकारी विकास सिंह ने कहा कि हम सभी जब तिरंगा लहराते हैं तब हम सभी को गर्व महसूस होता है ।हमें आजादी के लड़ाई में अपने प्राणों की को न्योछावर करने वाले शहीदों को कभी भूलना नही चाहिए ।कार्यक्रम में विशाल मिश्र भाजपा मोर्चा के ब्लॉक अध्यक्ष विशाल मिश्र, मुन्ना सिंह,एडीओ पंचायत रत्नेश सोनकर,राजेश सिंह, राकेश उपाध्याय,आशीष त्रिपाठी, आशीष सिंह, शशांक श्रीवास्तव,अंजना राय, दीप नारायण सोनक, अंकेश सरोज,सन्तोष त्यागी सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे।

मोतियाबिंद आपरेशन शिविर में 21 लोग चिहिन्त

जौनपुर। लायन्स क्लब व आर जे शंकरा आई हॉस्पिटल वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में नि :शुल्क नेत्र जांच मोतियाबिंद आपरेशन शिविर का आयोजन केयर सेंटर निकट कुत्तुपुर तिराहा पर किया गया। शिविर में 74 लोगों का नेत्र परीक्षण किया गया। इनमें से 21 मरीजों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चुना गया है, जिन्हें नि :शुल्क आपरेशन के लिए वाराणसी रवाना किया गया। शिविर में डॉ. अंकित और उनकी चिकित्सकीय टीम ने रोगियों की जांच की। संस्थाध्यक्ष राजीव श्रीवास्तव ने कहा कि इस शिविर का उद्देश्य वंचित और ग्रामीण व शहरी समुदायों को नि :शुल्क नेत्र जांच और नि :शुल्क मोतियाबिंद सर्जरी प्रदान करना है। इन मरीजों के लिए दवाइयां, चश्मा, भोजन, रहने और आने जाने की व्यवस्था भी बिल्कुल मुफ्त प्रदान की जाती है। मोहम्मद मुस्तफा, रितेश गुप्ता, डॉ चन्द्रकला मौर्य, वीरेंद्र मौर्य, डॉ मदन मोहन वर्मा, डॉ हस्सान महमूद, आदि उपस्थित रहे।

किषोरी को भगाने में युवक गिरफ्तार

जौनपुर। जलालपुर थाने की पुलिस ने 17 वर्षीय किशोरी को बहला–फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत संबंधित धाराओं में कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार, 12 अगस्त को किशोरी की मां ने जलालपुर थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 11 अगस्त को गांव का रहने वाला गोरख उर्फ गौरव उनकी पुत्री को त्रिलोचन बाजार से बहला–फुसलाकर अपने साथ ले गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। विवेचना के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 64(1) बीएनएस और 3ध्4 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए गोरख उर्फ गौरव पुत्र कैलाश, निवासी ककोरी, थाना जलालपुर को से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी की उम्र करीब 19 वर्ष है और उसके खिलाफ जलालपुर थाने में पहले से भी पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

बदलते दौर में मल्टी–स्किल पत्रकारिता जरूरी

जौनपुर। पूर्वांचल विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग में पत्रकारिता की बदलती चुनौतियों और मीडिया के बदलते स्वरूप पर विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। विभाग के पूर्व विद्यार्थी एवं इंडिया वॉइस चैनल के पूर्व प्रमुख, लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार बृजेश सिंह ने विद्यार्थियों को पत्रकारिता के बदलते दौर में तकनीकी दक्षता, लेखन, बोलने की कला और कैमरे के सामने प्रभावी प्रस्तुति के महत्व के बारे में जानकारी दी। कहा कि एक समय पत्रकारिता मुख्य रूप से अखबारों और फिर टेलीविजन तक सीमित थी। उस दौर में डिजिटल प्लेटफॉर्म का विस्तार नहीं था और प्रशिक्षण के अवसर भी सीमित थे। आज मीडिया का स्वरूप तेजी से बदल चुका है। डिजिटल मीडिया में गुणवत्तापूर्ण कंटेंट तैयार करने वाले प्रतिभाशाली लोगों की मांग बढ़ रही है ।उन्होंने कहा कि आज के दौर में मीडिया संस्थानों को मल्टी–स्किल प्रोफेशनल्स की आवश्यकता है। पहले जिस काम को करने के लिए चार लोगों की जरूरत होती थी, आज तकनीक के कारण कई काम एक ही व्यक्ति को करने पड़ रहे हैं। इसलिए पत्रकारिता के विद्यार्थियों को लेखन, बोलने, कैमरा फेसिंग, वीडियो निर्माण और डिजिटल कंटेंट तैयार करने सहित विभिन्न कौशलों में दक्ष होना चाहिए। विभाग के अध्यक्ष डॉ. मनोज मिश्र ने वरिष्ठ पत्रकार बृजेश सिंह का स्मृति चिह्न देकर स्वागत किया। धन्यवाद ज्ञापन डॉ. सुनील कुमार ने किया तथा संचालन डॉ. दिग्विजय सिंह राठौर ने किया।

भव्य तिरंगा रैली का किया आयोजन

जौनपुर। 'हर घर तिरंगा अभियान' के अंतर्गत सद्भावना पुल से कलेक्ट्रेट परिसर स्थित विकास भवन शहीद स्तंभ तक भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। विधान परिषद सदस्य बृजेश सिंह 'प्रिंशु', नगरपालिका परिषद की अध्यक्ष श्रीमती मनोरमा मौर्य, जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन., मुख्य विकास अधिकारी सहित जनपद के अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, पुलिस अधिकारी, शिक्षक–शिक्षिकाएं, छात्र–छात्राएं, युवा, स्वयंसेवक, पूर्व सैनिक, स्वयं सहायता समूहों की महिलाएँ, 'माय भारत' वालंटियर्स, अधिवक्ता, पत्रकार एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए। रैली से पूर्व सद्भावना पुल पर विभिन्न विद्यालयों के छात्र–छात्राओं, युवाओं एवं वालंटियर्स द्वारा 'हर घर तिरंगा' मानव श्रृंखला बनाकर आकर्षक आकृति बनाई गई, जो कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रही। मानव श्रृंखला के माध्यम से राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान, देशभक्ति एवं राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया। इसके उपरांत सभी प्रतिभागियों ने सफेद टी–शर्ट सफेद शर्ट धारण कर तथा हाथों में तिरंगा लेकर रैली में उत्साहपूर्वक सहभागिता की। रैली का शुभारंभ सामूहिक रूप से 'वंदे मातरम' के गायन के साथ हुआ। सद्भावना पुल से प्रारंभ हुई तिरंगा रैली निर्धारित मार्ग से होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर स्थित विकास भवन के पास शहीद स्तंभ तक पहुंची। रैली के दौरान प्रतिभागियों की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सद्भावना पुल सहित विभिन्न स्थानों पर पेयजल एवं फल की व्यवस्था की गई। जिला प्रशासन द्वारा यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था के समुचित प्रबंध किए गए, जिससे रैली शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित एवं भव्य रूप से सम्पन्न हुई।

प्रेम विवाह कर गांव लौटे युवक-युवती, पंचायत ने जताई आपत्ति, दोनों को गांव से बाहर भेजा

आर्यावर्त संवाददाता

बागपत। बागपत के झूंडपुर गांव में प्रेम विवाह करने के करीब चार महीने बाद लौटे युवक-युवती के गांव में रहने पर ग्रामीणों ने आपत्ति जताई। बुधवार को पंचायत में दोनों के गांव में रहने को लेकर चर्चा हुई, जिसके बाद उन्हें गांव से बाहर जाने को कहा गया। पंचायत के बाद युवक अपनी पत्नी के साथ गांव से चला गया। पुलिस के अनुसार, प्रेम विवाह को लेकर किसी को आपत्ति नहीं है और गांव में शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है।

झूंडपुर गांव निवासी जाट समाज के युवक का पड़ोस की हिंदू लुहार समाज की युवती से प्रेम प्रसंग था। ग्रामीणों के अनुसार, करीब छह महीने पहले दोनों गांव से चले गए थे। ग्रामीणों के समझाने पर युवक युवती को घर वापस छोड़ गया था।

इसके बाद युवती की विधवा मां ने उसे रिश्तेदारी में रहने के लिए भेज दिया। हालांकि, दोनों के बीच बातचीत जारी रही। कुछ समय बाद युवक फिर युवती को उसकी रिश्तेदारी से लेकर चला गया और दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। इसके बाद दोनों गांव से बाहर रहने लगे।

दो सप्ताह से गांव में रह रहे थे दंपती

ग्रामीणों के अनुसार, पिछले करीब दो सप्ताह से दोनों दोबारा गांव में आकर रहने लगे थे। इसकी जानकारी होने पर ग्रामीणों और युवती के परिजनों ने विरोध जताया। इसी मामले को लेकर बुधवार को गांव में पंचायत बुलाई गई। पंचायत में युवक और युवती के परिवार के लोग भी शामिल हुए। ग्रामीणों ने दोनों के गांव में रहने को लेकर आपत्ति जताई और कहा कि इससे अन्य युवक-युवतियों पर गलत प्रभाव पड़ सकता है।

पंचायत ने गांव से बाहर जाने का निर्णय लिया

पंचायत में पंचों ने दोनों को गांव से बाहर भेजने का निर्णय लिया। युवक के परिजनों ने पांच दिन का समय मांगा, जबकि पंचायत की ओर से एक सप्ताह का समय दिया गया। हालांकि, पंचायत खत्म होते ही युवक अपनी पत्नी के साथ गांव से चला गया।

पुलिस ने बताया- प्रेम विवाह पर किसी को आपत्ति नहीं

पंचायत की सूचना मिलने पर पुलिस ने टीम भेजकर मामले की जानकारी कराई। एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि दोनों के प्रेम विवाह करने पर किसी को आपत्ति नहीं है। दोनों के गांव में आकर रहने को लेकर लोगों ने पंचायत की थी। उन्होंने कहा कि गांव में शांतिभंग जैसी कोई स्थिति नहीं है।

युवती ने एसपी कार्यालय पर जहरीला पदार्थ

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास गुरूवार को न्यान न मिलने का आरोप लगाते हुए युवती ने जहर का सेवन कर आत्महत्या का प्रयास किया जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। उसे जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखकर वाराणसी के लिए रेफर किया गया है। बदलापुर थाना क्षेत्र के घनश्यामपुर गांव निवासी 19 वर्षीया महिमा तिवारी पुत्री रमेश चंद तिवारी ने आरोप लगाया कि गुरुवार को वह पुलिस अधीक्षक से मिलने गई थी। न्याय न मिलने का आरोप लगाते हुए उसने आवेश में आकर कीटनाशक का सेवन कर आत्महत्या का प्रयास किया। जैसे ही यह जानकारी लाइन बाजार थाना पुलिस को हुई तुरंत पुलिस ने उसे जिला अस्पताल पहुंचा कर भर्ती करवा दिया। यह भी बताया जा रहा है कि लगभग दो माह पूर्व

इसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को जेल भेज दिया था ।जबकि जिला अस्पताल में उपचार के दौरान महिमा तिवारी ने खुटहन थाना क्षेत्र के वीरमपुर गांव निवासी अशोक यादव नामक व्यक्ति के विरुद्ध भी दुष्कर्म किए जाने की बात कही है। युवती लाइन बाजार थाना क्षेत्र स्थित टीचर कॉलोनी में रहकर पढ़ाई करती है। घटना की जानकारी होने पर क्षेत्राधिकार नगर गोल्डी गुप्ता जिला अस्पताल पहुंचकर पीड़ति का हाल जाने। पुलिस द्वारा युवती के परिजनों को घटना की सूचना दी गई है। पुलिस ने बताया कि घटना में कार्रवाई को किया जा चुका है। खुटहन थानाध्यक्ष विक्रम लक्ष्मण सिंह ने मामले को लेकर बताया कि कुछ दिन पहले अशोक यादव के विरुद्ध आरोप लगाया गया था कि लाइन बाजार थाना पर लिखे गए मुकदमा उठा लेने के लिए धमकी दे रहा है। इस आरोप को लेकर भी मुकदमा लिखा गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

साइड लंज करते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, मिलेगा संतुलन

साइड लंज एक बेहतरीन एक्सरसाइज है, जो आपके पैरों और कूल्हों को मजबूत बनाने में मदद करती है। यह न केवल मांसपेशियों को टोन करती है, बल्कि संतुलन और स्थिरता भी बढ़ाती है। हालांकि, साइड लंज करते समय कुछ सामान्य गलतियां हो सकती हैं, जिनसे चोट लगने का खतरा बढ़ सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देंगे, जिनसे आप साइड लंज करते समय संतुलन बना सकते हैं और चोट से बच सकते हैं।

सही जूते पहनें

साइड लंज करते समय सही जूते पहनना बहुत जरूरी है। अच्छे पकड़ वाले जूते पहनें ताकि फिसलन न हो और पैर जमीन पर सही तरीके से टिक सकें।

सपाट सोल वाले जूते सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि ये जमीन पर बेहतर संपर्क बनाते हैं और फिसलने से बचाते हैं।

ऊंची एड़ी वाले जूते या चप्पल जैसे ढीले जूते न पहनें क्योंकि ये संतुलन बिगाड़ सकते हैं और चोट का कारण बन सकते हैं।

पैर फैलाने का तरीका सही रखें

साइड लंज करते समय पैर फैलाने का तरीका सही होना चाहिए। एक पैर को आगे और दूसरा पैर पीछे की ओर फैलाएं।

ध्यान रखें कि दोनों घुटने एक सीध में हों और पीछे वाला पैर पूरी तरह सीधा हो। इससे आपकी मांसपेशियां सही तरीके से काम करेंगी और चोट का खतरा कम होगा।

इसके अलावा इस स्थिति में शरीर का संतुलन भी बना रहता है, जिससे व्यायाम करना आसान हो जाता है।

शरीर का वजन सही तरीके से बांटे

साइड लंज करते समय शरीर का वजन सही तरीके से बांटना बहुत जरूरी है।

जब आप पीछे वाले पैर को मोड़ते हैं तो अपना वजन उस पैर पर डालें, जिससे आपको संतुलन बनाने में मदद मिलेगी। इससे आपके घुटनों पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा और चोट लगने का खतरा भी कम हो जाएगा।

इसके अलावा यह तरीका आपकी मांसपेशियों को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करेगा और आपको अधिक स्थिरता देगा।

हाथों की स्थिति पर ध्यान दें

हाथों की स्थिति भी साइड लंज करते समय अहम भूमिका निभाती है। अपने हाथों को कमर पर रखें या सामने फैलाएं ताकि आपको संतुलन बनाने में मदद मिले।

अगर आपके हाथ इधर-उधर घूमते रहें तो इससे संतुलन बिगड़ सकता है और गिरने का खतरा बढ़ जाता है।

इसके अलावा हाथों को सही स्थिति में रखने से आपके शरीर का केंद्र भी स्थिर रहता है, जिससे व्यायाम करना आसान हो जाता है और चोट लगने का खतरा कम हो जाता है।

धीरे-धीरे एक्सरसाइज करें

साइड लंज करते समय धीरे-धीरे गति बनाए रखना चाहिए। अचानक तेज गति से करने पर मांसपेशियां खींच सकती हैं या चोट लग सकती हैं।

इसलिए इसे धीरे-धीरे करें और हर कदम पर ध्यान दें। इससे न केवल आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी, बल्कि चोट लगने का खतरा भी कम होगा।

नियमित अभ्यास से आप इस एक्सरसाइज में माहिर हो जाएंगे और इसके सभी लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इन सुझावों को अपनाकर आप साइड लंज करते समय संतुलन बना सकते हैं।

दोपहर में की गई इन गलतियों कारण कम होने लगती है शरीर की ऊर्जा

दोपहर के समय ऊर्जा का स्तर अचानक गिरना एक आम समस्या है, जिसका कई लोगों को सामना करना पड़ता है। इसका मुख्य कारण हमारी दिनचर्या और खान-पान से जुड़ा होता है। अगर आप भी दोपहर में थकान और सुस्ती महसूस करते हैं तो यह लेख आपके लिए है। यहां हम कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे, जिन्हें सुधारकर आप अपनी ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं और पूरे दिन सक्रिय रह सकते हैं।

भारी और मसालेदार भोजन करना

दोपहर के समय भारी और मसालेदार भोजन करने से पाचन तंत्र पर अधिक दबाव पड़ता है, जिससे नींद आती है। इससे बचने के लिए हल्का और पौष्टिक भोजन करें, जैसे सलाद, दही या फल।

इनसे आपको जरूरी पोषक तत्व मिलेंगे और ऊर्जा भी बनी रहेगी। इसके अलावा पानी पीते रहें, ताकि आपका शरीर नमी से भरा रहे और आप तरोताजा महसूस करें।

इस तरह आप दोपहर में सुस्ती और थकान से बच सकते हैं।

चाय-कॉफी का अधिक सेवन कर लेना

चाय या कॉफी का अधिक सेवन करने से आपको अस्थायी ऊर्जा मिल सकती है, लेकिन यह लंबे समय तक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है।

इससे शरीर में जलन बढ़ती है और नींद भी प्रभावित होती है। बेहतर होगा कि आप दिनभर में सीमित मात्रा में ही इनका सेवन करें और इसके बजाय हर्बल चाय या नींबू पानी पिएं।

इससे आपका शरीर नमी से भरा रहेगा और आप तरोताजा महसूस करेंगे।

लगातार स्क्रीन इस्तेमाल करना

लैपटॉप या मोबाइल स्क्रीन पर लगातार काम करने से आंखों पर तनाव पड़ता है, जिससे सिरदर्द और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

इससे नींद आने की समस्या खड़ी हो जाती है। इससे बचने के लिए हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए अपनी आंखों को बंद करें या दूर देखें।

इसके अलावा स्क्रीन ब्रेक लेने के लिए उठकर थोड़ी देर टहलें या हल्की स्ट्रेचिंग करें। इससे आपकी आंखें आराम करेंगी और आप तरोताजा महसूस करेंगे।

पर्याप्त पानी न पीना

शरीर को नमी से भरा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी की कमी से भी थकान होती है। दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीना चाहिए, ताकि शरीर में नमी बनी रहे और ऊर्जा स्तर भी ठीक रहे।

इसके अलावा आप नारियल पानी या ताजे फलों का रस भी पी सकते हैं, जो न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर भी होते हैं।

इससे आपका शरीर नमी से भरा रहेगा और आप तरोताजा महसूस करेंगे।

कसरत न करना

काम करते समय बीच-बीच में हल्की-फुल्की कसरत करना बहुत फायदेमंद होता है। इससे मांसपेशियों में खिंचाव आता है और रक्त संचार बेहतर होता है।

आप कुर्सी पर बैठकर गर्दन घुमा सकते हैं, हाथ-पैर खींच सकते हैं या कुछ मिनट टहल सकते हैं। इससे आपका मन भी तरोताजा रहेगा और आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करेंगे।

इस तरह आप अपनी दिनचर्या में हल्की-फुल्की कसरत शामिल करके आसानी से अपनी ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं।

सरकारी से कितना गुना महंगे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल? मरीजों की जेब पर कितना बोझ?

भारतीय हेल्थ सेक्टर में बड़े बदलाव आए हैं लेकिन इलाज का बढ़ता और महंगा खर्च एक बड़ी चिंता है। सरकारी के मुकाबले प्राइवेट हॉस्पिटल में ये खर्चा औसतन 50000 से ऊपर आता है। जानें क्या कहती है रिपोर्ट

सरकारी अस्पताल के मुकाबले प्राइवेट में इलाज कराना लोगों को 8 से 15 गुना ज्यादा महंगा पड़ रहा है। नेशनल सैंपल सर्वे के 80वें राउंड के आंकड़ों के आधार पर LocalCircles ने ये रिपोर्ट जारी की है। आंकड़े कहते हैं कि आम परिवारों को सरकारी के मुकाबले प्राइवेट में औसतन 50508 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। जबकि सरकारी में ये खर्च महज 6631 रुपये है। देखा जाए तो प्राइवेट में इलाज कराना करीब 8 गुना ज्यादा है। इस हिसाब से भारत में इलाज का खर्च आम आदमी के लिए बहुत बड़ी टेंशन बनता जा रहा है।

इस सर्वे में उन परिवारों का एक्सपीरियंस शामिल है जिन्होंने बीते 3 सालों में हॉस्पिटल के खर्चे उठाए। सर्वे के मुताबिक कुछ मामलों में खर्च का ये फर्क करीब 15 गुना ज्यादा तक पहुंच सकता है। जानें क्या कहती है रिपोर्ट...।

लोकलसर्किल्स ने सर्वे के आधार पर देश के 306 जिलों के करीब 24000 लोगों से बात की। प्राइवेट हॉस्पिटल में बिलिंग, टेस्ट और मरीज के बेड से जुड़े सभी खर्चों इस रिपोर्ट में शामिल किए गए।

बिलिंग में ट्रांसपेरेंसी की कमी

प्राइवेट हॉस्पिटल में की जाने वाली बिलिंग भी लोगों की मुसीबतें बढ़ाती है। सर्वे में लोगों ने बताया कि उनसे बिल के अंदर गैरजरूरी डॉक्टर कंसल्टेशन चार्जिस लिए जाते हैं। करीब 40 फीसदी ने बताया कि डॉक्टरों की फीस भी जरूरत से ज्यादा ली जाती है। साथ ही लोग कहते हैं कि दवा और कंज्यूमेबल्स की मात्रा मनमुताबिक ली जाती है और ये ओवरबिलिंग की टेंशन बढ़ाती है। प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर की फीस, टेस्ट, कमरे का किराया और दूसरी चीजों को फाइनल बिल में काफी बढ़ा दिया जाता है।

कमरे और हॉस्पिटल के बेज का किराए में एकरूपता नहीं है और इसका कुल खर्च तेजी से बढ़ता है। इस कारण मरीज और उसका परिवार ये तय ही नहीं कर पाता है कि उसे कितने पैसे आखिर में भरने पड़ेंगे। बच्चे के जन्म के लिए प्राइवेट अस्पताल में खर्च औसतन 37630 रहा जबकि सरकारी में इसका खर्च सिर्फ 2299 रुपये रहा।

ये चीजें बढ़ा देती हैं फाइल बिल में खर्च

सर्वे कहता है कि लोगों प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर की फीस और सर्जरी को ही बड़ा खर्चा मानते हैं। इसमें रूम का रेंट, नर्सिंग चार्च, डॉक्टर की विजिट, दवा, टेस्ट, आईसीयू और हॉस्पिटल के कई दूसरी सेवाओं के अलग-अलग चार्ज भी शामिल हो सकते हैं।

संसद की एक समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्राइवेट अस्पतालों में इलाज सरकारी अस्पतालों की तुलना में पांच से 10 गुना तक महंगा है. समिति का कहना है कि प्रसव, कैंसर, हृदय रोग और गुर्दे के खराबी की स्थिति में यह अंतर और बढ़ जाता है.

सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कितना खर्चीला है

इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में एक और कमी की ओर इशारा किया है।समिति ने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से पिछले साल जनवरी से दिसंबर के बीच किए गए नेशनल सैंपल सर्वे के हवाले से कहा है कि निजी अस्पतालों और सरकारी अस्पलातों में इलाज के खर्च में भारी अंतर है। समिति ने कहा है कि प्राइवेट अस्पतालों में इलाज सरकारी अस्पतालों की तुलना में पांच से दस गुना तक अधिक महंगा है। समिति का कहना है कि प्रसव, कैंसर, हृदय रोग और गुर्दे के खराबी की स्थिति में यह अंतर साफ–साफ दिखाई देता है। समिति के मुताबिक भारत में किसी बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होने का औसत खर्च करीब 37,858 रुपये है, जबकि जेब से होने वाला खर्च करीब 34,064 रुपये है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में भर्ती होने का औसत खर्च 6,631 रुपये है जबकि निजी अस्पतालों में यह बढ़कर 50,508 रुपये हो जाता है। समिति का कहना है कि कैंसर, हृदय रोग और गुर्दे की खराबी जैसी गंभीर बीमारियों के मामले में यह अंतर और भी ज्यादा हो जाता है।

बीमा के बाद भी जेब पर बोझ

आजकल लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेकर चलते हैं ताकि उन्हें प्राइवेट में इलाज कराते समय पैसा खर्च करना न पड़े। सर्वे कहता है कि इसके बावजूद मरीजों का आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च (ओओपीई) कम नहीं हो रहा। इंश्योरेंस की मदद भी तब मिल पाती है जब मरीज को कम से कम 24 घंटे के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया जाए। इसके अलावा ओपीडी, डायग्नोस्टिक टेस्ट और महंगी-महंगी दवाओं पर खर्च खुद मरीज को ही करना पड़ता है।

इसलिए प्राइवेट और सरकारी में इलाज का खर्च कहीं गुना ज्यादा हो जाता है। नेशनल सैंपल सर्वे 2025 के मुताबिक देश में हेल्थ बीमा का दायरा भी बढ़ा है। ये ग्रामीण इलाकों में 47.4 फीसदी और शहरी इलाकों में करीब 44.3 फीसदी तक पहुंचा है।

छोटे क्लीनिक का बढ़ता चलन

भारत में बड़े अस्पताल तेजी से बढ़ रहे हैं और ये मेडिकल टूरिज्म से भी खूब पैसा कमा रहे हैं। लेकिन आम आदमी या परिवारों की छोटे क्लीनिक पर निर्भरता भी बढ़ी है। भारत के हेल्थ सेक्टर का बड़ा हिस्सा छोटे क्लीनिक, नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक सेंटर्स पर भी डिपेंड है।

सर्वे कहता है कि 60 फीसदी से ज्यादा इनपेशेंट केयर और करीब 70 फीसदी आउटपेशेंट केयर इसी नेटवर्क से जुड़ी है। इनकी कीमतों और दूसरी सर्विस से जुड़ी चीजों की निगरानी करना आसान नहीं है।

कितना होना चाहिए अस्पताल के कमरे का किराया

समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उसका मानना है कि कुछ निजी अस्पताल, विशेषकर महानगरों में स्थित निजी अस्पताल, अस्पताल में रहने के लिए भारी शुल्क वसूलते हैं। अस्पतालों के बिलिंग ढांचे का विश्लेषण करने के बाद समिति ने पाया है कि अस्पतालों के कमरे के किराए को तत्काल तर्कसंगत बनाना जरूरी है। समिति का कहना है कि अस्पताल के कमरे के शुल्क एक समान नहीं होते है। समिति का कहना है कि भौगोलिक क्षेत्रों के साथ–साथ एक ही क्षेत्र के अस्पतालों में भी बुनियादी ढांचे, सेवा स्तर और परिचालन लागत में अंतर के कारण किराया अलग–अलग होते हैं। समिति ने सिफारिश की है कि किसी अस्पताल के कमरे का किराया अस्पताल के आसपास के क्षेत्र में स्थित तीन सितारा होटलों के कमरे के शुल्क से अधिक नहीं होना चाहिए। समिति ने सिफारिश की है कि मूल कमरे के शुल्क में रेजिडेंट डॉक्टर की लागत, नर्सिंग लागत, उपभोग्य सामग्रियों की लागत, भोजन शुल्क और कपड़े धोने का शुल्क को जोड़ा जा सकता है, ताकि कुल लागत तर्कसंगत हो जाए

हैकर ग्रुप के दावों पर एचसीएलटेक का जवाब, कहा- सिस्टम में सेंधमारी के कोई सबूत नहीं, ग्राहक सेवाएं सुरक्षित

अनुरूप सार्वजनिक

देश की दिग्गज आईटी सर्विस कंपनी एचसीएलटेक ने सोमवार को स्पष्ट किया कि एक हैकर समूह द्वारा कर्मचारियों से जुड़ा डेटा लीक होने के दावों की जांच में अब तक कंपनी के सिस्टम में किसी तरह की सेंधमारी के सबूत नहीं मिले हैं। कंपनी ने कहा कि शुरुआती जांच के अनुसार न तो उसके आईटी सिस्टम प्रभावित हुए हैं और न ही किसी ग्राहक के प्रोजेक्ट या डेटा पर इसका असर पड़ा है।

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में एचसीएलटेक ने बताया कि हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में एक हैकर ग्रुप के दावे का उल्लेख किया गया था, जिसमें कंपनी के कर्मचारियों से संबंधित कुछ डेटा के संभावित सार्वजनिक होने की बात कही गई थी। इन दावों के बाद कंपनी ने तत्काल जांच शुरू की।

कंपनी ने कहा, प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि कथित डेटा सीमित मात्रा में हो सकता है और यह कई वर्ष पुराना प्रतीत होता है।

एचसीएलटेक ने यह भी स्पष्ट किया कि अब तक उसे अपने किसी भी सिस्टम में अनधिकृत प्रवेश या साइबर सुरक्षा उल्लंघन का कोई प्रमाण नहीं मिला है। साथ ही कंपनी के ग्राहकों के साथ चल रही परियोजनाओं या उनके डिजिटल वातावरण पर किसी प्रकार का प्रभाव भी सामने नहीं आया है।

कंपनी ने कहा कि मामले की विस्तृत जांच अभी जारी है और यदि समीक्षा के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी सामने आती है, तो उसे नियामकीय आवश्यकताओं के किया जाएगा।

एचसीएलटेक ने अपने बयान में कहा, साइबर सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और हमें सौंपी गई सूचनाओं की सुरक्षा के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

यह बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में देश की एक अन्य बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) को भी इसी तरह के दावों पर स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा था। टीसीएस ने भी कहा था कि उसे अपनी जांच में कंपनी के सिस्टम या ग्राहकों के डिजिटल वातावरण में किसी तरह की सेंधमारी का कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं मिला।

टीसीएस के अनुसार, जिन सूचनाओं का उल्लेख साइबर खुफिया अलर्ट्स में किया गया था, वे चार वर्ष से अधिक पुरानी थीं और केवल बुनियादी कर्मचारी जानकारी तक सीमित थीं। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया था कि ग्राहक डेटा, ग्राहक सिस्टम या कंपनी के परिचालन सिस्टम किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हुए हैं।

टीसीएस ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया था कि कथित हमलावर ने पासवर्ड स्प्रेइंग और मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (एमएफए) फटीग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करने का दावा किया था। हालांकि जांच में इन दावों की पुष्टि नहीं हुई।

इस बीच, एचसीएलटेक के शेयरों में सकारात्मक रुख देखने को मिला। खबर लिखे जाने के समय कंपनी के शेयर एनएसई पर 0.57 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,365 रुपए के स्तर पर कारोबार करते नजर आए।

यूपीआई भुगतान बंद कर सकते हैं पेट्रोल पंप संचालक, बैंक खाते फ्रीज होने से भड़के डीलरों की चेतावनी

तमिलनाडु के पेट्रोल पंप संचालकों ने डिजिटल भुगतान, विशेषकर यूपीआई ट्रांजैक्शन, को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो राज्य भर के पेट्रोल पंप यूपीआई और अन्य कैशलेस भुगतान स्वीकार करना बंद कर सकते हैं। डीलरों का आरोप है कि साइबर अपराध जांच के दौरान उनके बैंक खातों को फ्रीज कर दिया जाता है, जबकि विवादित लेनदेन में उनकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती।

तमिलनाडु पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन (टीएनपीडीए), जो राज्य के लगभग 5,000 पेट्रोल पंपों का प्रतिनिधित्व करती है, ने इस मामले में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय से हस्तक्षेप की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि डिजिटल भुगतान से जुड़े बढ़ते जोखिमों के कारण पेट्रोल पंप संचालकों के लिए कैशलेस भुगतान सुविधा जारी रखना मुश्किल होता जा रहा है।

मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में टीएनपीडीए के अध्यक्ष के.पी. मुरली ने कहा कि पेट्रोल पंप संचालकों को साइबर अपराध जांच में घसीटा जा रहा है, जबकि वे केवल ग्राहकों से पेट्रोल या डीजल की बिक्री के बदले वैध भुगतान प्राप्त करते हैं। एसोसिएशन के अनुसार, पेट्रोल पंप संचालकों के पास यह जांचने की कोई व्यवस्था नहीं होती कि यूपीआई या अन्य डिजिटल माध्यम से भुगतान करने वाला ग्राहक कौन है अथवा उसके द्वारा भेजी गई राशि पहले किसी कथित साइबर धोखाधड़ी से जुड़े खाते से होकर गुजरी है या नहीं। राज्य में डिजिटल भुगतान का उपयोग तेजी से बढ़ा है। एक औसत पेट्रोल पंप पर प्रतिदिन 200 से 500 डिजिटल लेनदेन होते हैं, जबकि कई आउटलेट्स पर कुल आय का आधे से अधिक हिस्सा यूपीआई और अन्य कैशलेस माध्यमों से आता है।

डीलरों का कहना है कि समस्या तब पैदा होती है जब किसी ग्राहक द्वारा किया गया भुगतान बाद में साइबर अपराध जांच के दायरे में आ जाता है। जांच एजेंसियों के निर्देश पर बैंक संबंधित राशि पर रोक लगा देते हैं या कई मामलों में पूरे बैंक खाते को फ्रीज कर देते हैं।

पेट्रोल पंप संचालकों का तर्क है कि किसी एक संदिग्ध लेनदेन के कारण पूरे कारोबारी खाते को फ्रीज करना उचित नहीं है। इससे उनके दैनिक संचालन पर गंभीर असर पड़ता है, क्योंकि ईंधन खरीदने, कर्मचारियों का वेतन देने और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए बैंकिंग सेवाओं का निर्बाध संचालन जरूरी होता है।

एसोसिएशन ने पुलिस कार्रवाई को लेकर भी चिंता जताई है। उसका आरोप है कि कुछ मामलों में पेट्रोल पंप संचालकों को सुबह-सुबह पूछताछ के लिए ले जाया गया, जबकि शुरुआत में उन्हें यह भी नहीं बताया गया कि किस लेनदेन की जांच की जा रही है।

टीएनपीडीए का कहना है कि अधिकृत डिजिटल भुगतान माध्यमों के जरिए भुगतान स्वीकार करने वाले व्यापारियों को केवल इस कारण संदिग्ध नहीं माना जाना चाहिए कि बाद में किसी लेनदेन पर साइबर अपराध की जांच शुरू हो गई।

एसोसिएशन ने राज्य सरकार से ऐसी सुरक्षा व्यवस्था बनाने की मांग की है, जिससे वैध व्यवसायियों के बैंक खातों को बिना पर्याप्त आधार के फ्रीज न किया जाए और उन्हें अनावश्यक पुलिस कार्रवाई का सामना न करना पड़े।

डीलरों ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यावहारिक समाधान नहीं निकाला गया, तो तमिलनाडु के पेट्रोल पंप यूपीआई और अन्य डिजिटल भुगतान सुविधाएं बंद कर नकद लेनदेन की ओर लौटने के लिए मजबूर हो सकते हैं।

एसबीआई बैंक लॉकर से 50 लाख के जेवर गायब, सालों तक कटता रहा किराया ; बिना चाबी के कैसे हुआ खेल ?

कानपुर ,12 अगस्त ,। अगर आप भी अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई और कीमती जेवरात को बैंक लॉकर में यह सोचकर रखते हैं कि वहां वे सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, तो कानपुर का यह हैरान करने वाला मामला आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। शहर के स्वरूप नगर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में एक ऐसा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसने बैंकिंग सिस्टम की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां एक महिला के लॉकर से 50 लाख रुपये के पुश्तैनी जेवरात रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। पीड़िता की शिकायत पर कानपुर पुलिस ने बैंक मैनेजर और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

यह पूरा मामला कौशलपुरी की रहने वाली रश्मि अरोड़ा से जुड़ा है। उन्होंने साल 2003 में स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (जिसका बाद में एसबीआई में विलय हो गया) में खाता खुलवाकर लॉकर नंबर-23 लिया था। साल 2011 में पति के निधन के बाद रश्मि अपनी बेटी के पास लखनऊ शिफ्ट हो गईं। इस लंबे समय के दौरान उनके बचत खाते से लॉकर का सालाना किराया नियमित रूप से कटता रहा, जिससे उन्हें पूरा भरोसा था कि उनकी जमा-पूंजी सुरक्षित है। लेकिन करीब चार महीने पहले जब वह बैंक पहुंचीं, तो स्टाफ ने यह कहकर उनके होश उड़ा दिए कि उनके नाम पर कोई लॉकर ही दर्ज नहीं है। काफी मिन्नतों और रिकॉर्ड खंगालने के बाद आखिरकार उनका लॉकर बैंक में मिल गया।

लॉकर मिलने के बाद जब 27 जुलाई को बैंक कर्मचारियों की मौजूदगी में इसे खोला गया, तो रश्मि के पैरों तले जमीन खिसक गई। लॉकर पूरी तरह से खाली था और उसमें रखे 50 लाख के कीमती व पुश्तैनी आभूषण गायब थे। महिला ने तुरंत बैंक प्रबंधन और कर्मचारियों पर साजिश के तहत जेवर हड़पने का आरोप लगाते हुए पुलिस की शरण ली। कानपुर पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर स्वरूप नगर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब रश्मि 2011 के बाद पहली बार बैंक आई थीं और उनकी चाबी उनके ही पास थी, तो उनकी गैर-मौजूदगी में लॉकर का ताला आखिर किसने और कैसे खोला। पुलिस अब बैंक के दस्तावेजों और कर्मचारियों की भूमिका की गहनता से जांच कर रही है।

चंदे के पैसे से व्हाइट हाउस का काम, ट्रंप का 900 मिलियन डॉलर खर्च करने का प्लान

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की व्हाइट हाउस को आधुनिक अवतार देने वाले प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत फिर से बढ़ गई है। द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट और प्लानिंग दस्तावेजों की समीक्षा करने पर यह बात सामने आई है कि व्हाइट हाउस परिसर में प्रस्तावित निर्माण परियोजनाओं पर कुल खर्च कम से कम 927 मिलियन डॉलर हो सकता है।

इन परियोजनाओं में सबसे चर्चित ईस्ट विंग की जगह प्रस्तावित विशाल बॉलरूम है। इसके अलावा लाफायेट स्क्वायर में अपग्रेड, हेलीपैड, नया विजिटर स्क्रीनिंग सेंटर और सुरक्षा से जुड़ी अन्य सुविधाओं का निर्माण भी योजना का हिस्सा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, प्रशासन ने इन परियोजनाओं के लिए सीधे कांग्रेस से पूरी राशि मंजूर कराने के बजाय अलग-अलग सरकारी एजेंसियों और निजी दानदाताओं से मिले पैसों को एक खाते में ट्रांसफर किया है। इस खाते का इस्तेमाल आम तौर पर व्हाइट हाउस के नियमित रखरखाव और मरम्मत के लिए किया जाता है।इस खाते को व्हाइट हाउस रिपेयर और रिस्टोर्टेशन के नाम से जाना जाता है।

कांग्रेस इस खाते के लिए पिछले कई सालों से सालाना करीब 2।5 मिलियन डॉलर की राशि को मंजूरी देती रही है। लेकिन ट्रंप के कार्यकाल में इसमें अब तक करीब 875 मिलियन डॉलर ट्रांसफर किए जाने की बात सामने आई है।दस्तावेजों के मुताबिक, इसमें करीब 500 मिलियन डॉलर सरकारी एजेंसियों से, 305 मिलियन डॉलर निजी दान से और लगभग 70 मिलियन डॉलर ऐसे स्रोतों से आए हैं जिनकी पहचान सामने नहीं आ पाई है।

सीक्रेट सर्विस के पैसे का भी इस्तेमाल?

रिपोर्ट के मुताबिक, इस फंड में सबसे बड़ा सरकारी ट्रांसफर अमेरिकी सीक्रेट सर्विस और व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस से आया। सीक्रेट सर्विस से करीब 415 मिलियन डॉलर जून में ट्रांसफर किए गए। यह उस समय हुआ जब कांग्रेस में ईस्ट विंग और विजिटर स्क्रीनिंग सुविधा के लिए 400 मिलियन डॉलर की अलग फंडिंग को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी। ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि इन पैसों का इस्तेमाल सुरक्षा जरूरतों के लिए किया जा रहा है। प्रशासन के मुताबिक, ईस्ट विंग मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट में सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना, ड्रोन से सुरक्षा और अन्य सुरक्षा सुविधाएं शामिल हैं, जिसमें इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा।

ट्रंप प्रशासन का असमान्य फैसला

विशेषज्ञों का कहना है कि पहले से किसी स्वीकृत सरकारी फंड को इस तरह दूसरे खाते में ट्रांसफर करके बड़े निर्माण प्रोजेक्ट पर खर्च करना सामान्य नहीं है। यह एक तरीके से चंदे के पैसे से व्हाइट हाउस के निर्माण प्रोजेक्ट को पूरा करने जैसा है।अमेरिकी इतिहास में एक तरह से पहला मामला है। बता दें कि अमेरिकी संविधान के तहत सरकारी धन खर्च करने का अधिकार मुख्य रूप से कांग्रेस के पास है।

व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट देंगी इस्तीफा, ट्रंप ने बताया क्या होगा अगला रोल

वॉशिंगटन, एजेंसी। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट महीने के अंत में अपने पद से इस्तीफा देंगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसकी जानकारी देते हुए बताया कि प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट महीने के आखिर में अपना पद छोड़ देंगी ताकि वे अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिता सकें।

लेविट ने भी X पर एक लंबी पोस्ट में अपने जाने की पुष्टि की है। लेविट ने अपने फैसले को खट्टा-मीठा बताते हुए कहा कि उन्होंने यह डिसीजन तब लिया जब वे प्रेस सेक्रेटरी के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों और अपने दो छोटे बच्चों की मां के तौर पर अपनी भूमिका के बीच संतुलन नहीं बना पा रही हैं।

लेविट ने कहा कि डेढ़ साल तक व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी के तौर पर काम करना उनके लिए जीवन भर का सम्मान और रोमांचक अनुभव रहा। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें वेस्ट विंग में काम करने, राष्ट्रपति के साथ यात्रा करने और व्हाइट हाउस के ब्रीफिंग रूम से प्रशासन का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला।

दो बच्चों की मां बनने के बाद लिया पद छोड़ने का फैसला

लेविट ने कहा कि व्हाइट हाउस की सबसे अधिक मांग वाली सार्वजनिक भूमिकाओं में से एक को निभाते हुए दूसरी बार मां बनना उनके जीवन का सबसे संतोषजनक लेकिन चुनौतीपूर्ण दौर रहाय मई में उन्होंने अपनी दूसरी संतान, बेटी को जन्म दिया था और हाल ही में मातृत्व अवकाश के बाद व्हाइट हाउस लौटी थीं।

उन्होंने कहा कि बेटी के जन्म के बाद काम पर लौटने के बाद उन्हें लगातार यह महसूस हुआ कि अगर वह प्रेस सेक्रेटरी की जिम्मेदारियों के लिए जरूरी समय, ऊर्जा और ध्यान देती रहेंगी तो अपने दोनों छोटे बच्चों को वह समय नहीं दे पाएंगी, जिसके वे हकदार हैं।

ट्रंप के साथ आगे भी जुड़ी रहेंगी लेविट

पद छोड़ने के बावजूद लेविट ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी से अलग नहीं होंगी। ट्रंप ने उन्हें बाहर से अपने प्रमुख सलाहकारों में से एक के तौर पर काम करने को कहा है। लेविट ने भी स्पष्ट किया कि वह आगे रिपब्लिकन पार्टी और ट्रंप के राजनीतिक एजेंडे की मुखर समर्थक बनी रहेंगी।

बनी थी व्हाइट हाउस की सबसे युवा प्रेस सेक्रेटरी

जनवरी 2025 में ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद 28 साल की उम्र में कैरोलिन लेविट व्हाइट हाउस की इतिहास की सबसे कम उम्र की प्रेस सेक्रेटरी बनी थीं। इससे पहले वह ट्रंप के 2024 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान में नेशनल प्रेस सेक्रेटरी के तौर पर काम कर चुकी थीं। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान भी वह व्हाइट हाउस प्रेस ऑफिस का हिस्सा रही थीं।

ट्रंप ने की लेविट की तारीफ

ट्रंप ने लेविट के पद छोड़ने की घोषणा करते हुए उन्हें अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि वह लेविट के फैसले को पूरी तरह समझते और उसका सम्मान करते हैं। ट्रंप ने कहा कि लेविट अब उनके प्रमुख बाहरी सलाहकारों में से एक होंगी और रिपब्लिकन पार्टी में प्रभावशाली आवाज के तौर पर काम करती रहेंगी। उन्होंने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान समेत व्हाइट हाउस और अपने राजनीतिक अभियानों में लेविट के काम की भी तारीफ की।

तालिबान ने UN के दो अधिकारियों को हिरासत में लिया, ना आरोप बताया और ना किसी से मिलने की इजाजत

संयुक्त राष्ट्र, एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि अफगानिस्तान के तालिबान शासकों ने देश में संयुक्त राष्ट्र (UN) के पॉलिटिकल मिशन के 2 अफगान सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। हालांकि ये गिरफ्तारियां कुछ दिन पहले हुई हैं और इन लोगों के बारे में अभी कोई लेटेस्ट जानकारी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने इन दोनों लोगों की तुरंत रिहाई की मांग की है।

UN के डिप्टी प्रवक्ता फरहान हक ने UN पत्रकारों को बताया कि तालिबान के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस ने रविवार को पश्चिमी शहर हेरात में इन 2 कर्मचारियों को हिरासत में लिया। उन्होंने बताया कि UN मिशन को इन दोनों लोगों पर लगे आरोपों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है और न ही वे उनसे मिल सके हैं।

'UN अधिकारियों के विशेष छूट का पालन हो'

उन्होंने कहा कि मिशन ने तालिबान शासकों से "संयुक्त राष्ट्र और उसके अधिकारियों को मिलने वाले विशेषाधिकारों और छूट का पालन सुनिश्चित करने" को कहा है। तालिबान ने 15 अगस्त, 2021 को अफगानिस्तान की सत्ता पर तब कब्जा जमा लिया था, जब दो दशक तक चली लंबी लड़ाई के बाद अमेरिकी और NATO सेनाएं देश छोड़कर वहां से वापस चली गई थीं।

सत्ता पर कब्जा जमाने के कुछ ही समय बाद ही तालिबान ने लड़कियों के सेकेंडरी स्कूलों में जाने पर रोक लगा दी और बाद में इन प्रतिबंधों को हायर एजुकेशन तक बढ़ा दिया। यही नहीं रोजगार और अन्य क्षेत्रों तक पाबंदी लगा दी गई, जिससे महिलाएं और लड़कियों की सार्वजनिक जीवन में भागीदारी लगभग खत्म हो गई।

पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान का संघर्ष

UN सुरक्षा परिषद की ओर से UN मिशन के काम में अफगान लोगों के लिए मानवीय मदद को बढ़ावा देना और उसका समर्थन करना, मानवाधिकारों को बढ़ावा देना, महिलाओं और लड़कियों के लिए समानता, समावेशी शासन और आर्थिक स्थिरता भी शामिल होता है।

इन दोनों लोगों को तब हिरासत में लिया गया जब गरीबी से जूझ रहे इस एशियाई देश में मानवीय संकट लगातार गहराता जा रहा है। साथ ही पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहद खराब दौर में चल रहे हैं। इस समय तालिबान सेनाएं पाकिस्तानी सेनाओं के साथ सीमा-पार की जंग में उलझी हुई हैं।

अफसरों को तुरंत रिहा करे तालिबान : HRW

इस साल फरवरी में दोनों के बीच संघर्ष तब तेजी से बढ़ गईं जब अफगान सेनाओं ने अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के जवाब में पाकिस्तान में छापेमारी की। बाद में इस्लामाबाद ने घोषणा की कि वह "खुली जंग" के लिए तैयार है।

ह्यूमन राइट्स वॉच में अफगानिस्तान रिसर्चर फरिश्ता अब्बासी ने कहा कि दोनों लोगों की हिरासत "पूरे अफगानिस्तान में UN के काम और जीवन बचाने वाली सहायता पहुंचाने की उसकी क्षमता के लिए गंभीर संकट पैदा करती है।" उन्होंने कहा, "तालिबान अधिकारियों को हिरासत में लिए गए लोगों को तुरंत रिहा करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी सहायता एजेंसियां बिना किसी डर या दखल के काम कर सकें।"

जेल में फोन पर बात करते दिखे रेवन्ना, वीआईपी बैरक छिनी अब आम कैदियों के साथ काटेंगे उम्रकैद

नई दिल्ली, एजेंसी। बलात्कार के एक मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु की सेंट्रल जेल के वीआईपी सेक्शन से निकालकर आम कैदियों वाले सामान्य सेल में भेज दिया गया है। इसके पीछे की वजह ये है कि उनकी बैरक से एक 'एंड्रॉयड' मोबाइल फोन बरामद हुआ था। कल यानी बुधवार शाम को इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था।

इस 17 सेकंड के वीडियो में रेवन्ना को जेल की कोठरी में मोबाइल फोन पर बात करते हुए दिखाया गया है। फोन मिलने की खबर के बाद रेवन्ना को करीब 20 अन्य कैदियों के साथ एक सेल में डाल दिया गया है। उन्हें अब अनिवार्य जेल वर्दी पहनने और जेल के पुस्तकालय में काम करने का आदेश दिया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी सख्त सुरक्षा वाली जेल में फोन कैसे पहुंच गया?

इस पूरे मामले में जेल एवं सुधार विभाग के डीजीपी आलोक कुमार ने बुधवार को बताया कि सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CBC) की छापेमारी के दौरान रेवन्ना की बैरक से यह मोबाइल बरामद किया गया। सीसीबी ने मंगलवार दोपहर जेल में छापेमारी की थी। प्रज्वल रेवन्ना की बैरक से एक 'एंड्रॉयड' फोन जब्त किया गया है। उन्होंने बताया कि जेल अधिकारियों ने छह अगस्त को भी रेवन्ना की बैरक की तलाशी ली थी, लेकिन उस समय वहां कोई प्रतिबंधित सामान नहीं मिला था। आलोक कुमार ने बताया कि सहायक अधीक्षक ईरन्ना को निलंबित कर दिया गया है, जबकि जेल अधीक्षक अंशुकुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। घटना की विस्तृत जांच की जा रही है।

रेवन्ना के वीडियो पर कर्नाटक में सियासी घमासान

दरअसल, यह विवाद मानसून सत्र से ठीक एक दिन पहले सामने आया है, इसलिए इस पर सियासी रंग भी चढ़ गया है। विपक्षी भाजपा और जेडी(एस) ने कर्नाटक के योजना एवं सांख्यिकी मंत्री बी। नागेंद्र के इस्तीफे के बाद सदन की कार्यवाही रोकने की धमकी दी है।

बलात्कार के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे रेवन्ना

बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री एच। डी। देवेगौड़ा के पोते और जनता दल (सेक्युलर) के नेता एच। डी। रेवन्ना के बेटे प्रज्वल रेवन्ना को यौन उत्पीड़न के मामलों के सिलसिले में मई 2024 में गिरफ्तार किया गया था और बाद में दुष्कर्म के एक मामले में दोषी ठहराया गया। बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने अगस्त 2025 में प्रज्वल को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से वह परप्पना अग्रहारा जेल में बंद हैं। रेवन्ना ने 2019 से 2024 तक लोकसभा में हासन का प्रतिनिधित्व किया।

सड़क बनाने वाले इंजीनियरों को ही नहीं पता कैसे बनाना है रोड, 52% को नहीं मिली ट्रेनिंग

नई दिल्ली, एजेंसी। सड़क पर चलते हुए हम अक्सर फुटपाथ, साइकिल ट्रैक, सुरक्षित क्रॉसिंग और दिव्यांगों के लिए आसान रास्ते जैसी सुविधाओं को सड़क की बुनियादी जरूरत मानते हैं, लेकिन जिन इंजीनियरों के हाथों में इन सड़कों का डिजाइन और निर्माण है, उनमें से बड़ी संख्या को सुरक्षित और पैदल यात्री-अनुकूल सड़क बनाने की बाकायदा ट्रेनिंग ही नहीं मिली। कोयंबटूर नगर निगम के 42 इंजीनियरों से सर्वे के लिए संपर्क किया गया, जिसमें से 26 इंजीनियरों ने रिस्पॉन्स किया, जिसमें सामने आया कि 52% को स्ट्रीट डिजाइन पर कोई प्रशिक्षण नहीं मिला। चौंकाने वाली बात यह है कि 97% इंजीनियर सड़क परियोजनाओं से जुड़े हैं, फिर भी सुरक्षित सड़क और नॉन-मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट यानी पैदल-साइकिल सुविधाओं का व्यावहारिक ज्ञान सीमित है। जुलाई 2021 की GIZ-CCMC रिपोर्ट बताती है कि सड़क सुरक्षा की चुनौती सिर्फ डिजाइन की नहीं, बल्कि प्रशिक्षण, मानकों और विभागीय समन्वय की भी है। सर्वे में शामिल 97% इंजीनियर किसी न किसी रूप में सड़क परियोजनाओं से जुड़े पाए गए। डिजाइन तैयार करने से लेकर गुणवत्ता जांच और साइट निरीक्षण तक, लेकिन इसके बावजूद 65% से ज्यादा इंजीनियरों ने माना कि वे NMT यानी नॉन-मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट (पैदल यात्री और साइकिल सुविधाएं) से जुड़ी परियोजनाओं पर काम नहीं करते। यानी सड़कें बनती तो रोज हैं मगर पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों को ध्यान में रखकर डिजाइन करने का अनुभव बेहद सीमित है। रिपोर्ट के मुताबिक केवल 28% इंजीनियरों को पैदल और साइकिल सुविधाओं से जुड़ा व्यावहारिक ज्ञान है और वे इसे अपने रोजमर्रा के काम में इस्तेमाल करते हैं। बाकी या तो पढ़ाई/प्रशिक्षण के दौरान सतही जानकारी हासिल कर चुके हैं या पूरी तरह अनजान हैं। 'सुरक्षित सड़कों' के सिद्धांत को लेकर स्थिति और भी गंभीर है। NMT परियोजनाओं पर काम करने वाले सिर्फ 9% इंजीनियर ही इन सिद्धांतों से पूरी तरह परिचित पाए गए। इसके अलावा दिव्यांगजन-अनुकूल (बैरियर-फ्री) डिजाइन की व्यावहारिक समझ भी केवल 35% इंजीनियरों के पास है और IRC व UTTIPEC जैसे राष्ट्रीय मानकों को नियमित रूप से इस्तेमाल करने वाले सिर्फ 45% हैं। रिपोर्ट का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि 52% इंजीनियरों को अब तक स्ट्रीट डिज़ाइन पर कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। नौकरी में भर्ती के समय की स्थिति और खराब है।

'मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है', होंठों पर किस करने का वीडियो वायरल होने पर निकिता रावल ने दी प्रतिक्रिया

निकिता रावल का वीडियो वायरल होने के बाद कई फैंस ने उनका सपोर्ट किया है। इस पर अभिनेत्री ने प्रतिक्रिया दी है। आइए जानते हैं पूरा मामला।

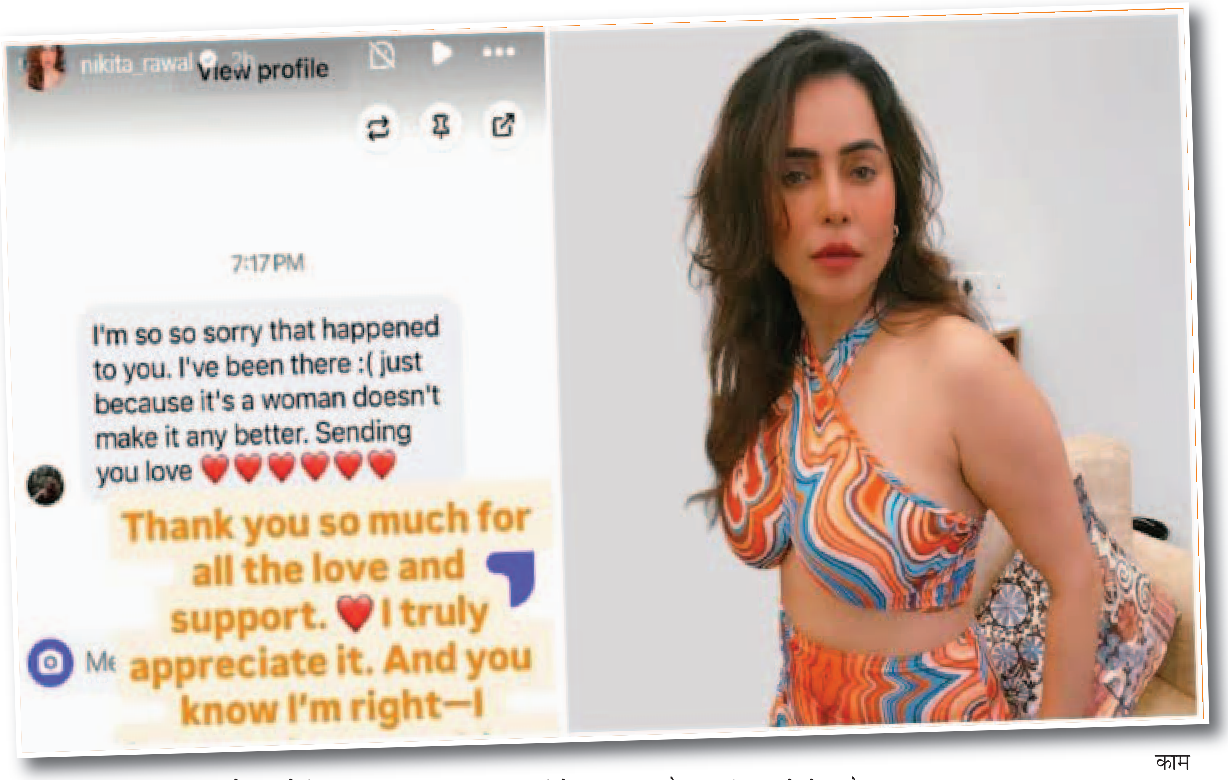

आठ अगस्त को अभिनेत्री निकिता रावल उस वक्त चर्चा में आ गईं, जब रेड कार्पेट पर एक महिला फैन ने अचानक उनके होंठों पर चूम लिया। इससे एक्ट्रेस हैरान और असहज हो गईं। यह घटना वीडियो में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिससे यूजर्स के बीच इस पर खूब चर्चा होने लगी।

वायरल वीडियो पर निकिता की प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के कुछ दिनों बाद, 12 अगस्त को निकिता ने इस घटना पर प्रतिक्रिया दी। एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर देश भर के फैंस से मिले सपोर्ट वाले मैसेज के स्क्रीनशॉट शेयर किए। कई लोगों ने निकिता के प्रति अपना समर्थन जताया और घटना के बाद उन्हें प्यार भेजा।

निकिता ने फैन का अदा किया शुक्रिया

मैसेज का जवाब देते हुए, निकिता ने विवाद के दौरान साथ देने के लिए अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिखा, 'इतने प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इसकी तारीफ करती हूं। आप जानते हैं कि मैं सही हूं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। मैं हमेशा सच के साथ खड़ी रहूंगी।'

एक फैन ने निकिता के सपोर्ट में लिखा कि वह उस महिला फैन को सजा देते। इस पर निकिता ने बस इतना कहा, 'आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद।'

वीडियो में क्या है?

वायरल वीडियो के अनुसार, महिला फैन ने पहले निकिता के गाल पर किस किया, फिर उन्हें अपनी ओर खींचा और होंठों पर किस किया। निकिता इस अचानक हुई हरकत से चौंक गईं। उन्हें उस फैन को रोकने और दूर धकेलने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता था।

निकिता का वर्कफ्रंट

निकिता ने बॉलीवुड और साउथ इंडियन, दोनों तरह की फिल्मों में काम किया है। उनकी फिल्मों में 'ब्लैक एंड व्हाइट', 'मिस्टर हॉट मिस्टर कूल', 'द हीरो- अभिमन्यु', 'अम्मा की बोली', 'गरम मसाला', 'क्यूट कमीना' और अन्य शामिल हैं।

वह जल्द ही 'रोटी कपड़ा और रोमांस' में नजर आएंगी, जिसमें वह अरशद वारसी और चंकी पांडे के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी।

वामिका गब्बी के हाथ लगी ऋ षभ शेट्टी की फिल्म जय हनुमान, जल्द शुरू करेंगी शूटिंग

वामिका गब्बी अपनी हालिया रिलीज फिल्म डीसीः द ब्लडी वैलेंटाइन को लेकर खबरों में छाई हैं। इस बीच खबर है कि उनके हाथ एक बड़ी फिल्म लगी है, जिसमें कांतारा अभिनेता ऋषभ शेट्टी नजर आएंगे। दरअसल, पिछले साल आई कांताराः चैप्टर 1 की सफलता के बाद शेट्टी अपनी अगली परियोजना जय हनुमान में व्यस्त चल रहे हैं, जो एक पौराणिक महाकाव्य होगी। अब इस परियोजना में उनके साथ वामिका भी जुड़ गई हैं, जिसका निर्देशन प्रशांत वर्मा कर रहे हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, पौराणिक महाकाव्य जय हनुमान में वामिका के किरदार को गुप्त रखा गया है, लेकिन वह एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली किरदार निभाती हुई नजर आएंगी।

बताया जा रहा है कि अभिनेत्री पहली बार पौराणिक कथाओं, एक्शन और भक्ति से भरपूर इस गाथा का हिस्सा बनने के लिए बेहद उत्साहित हैं और जल्द ही हैदराबाद में इसकी शूटिंग शुरू करेंगी।

ये परियोजना साल 2024 में आई अभिनेता तेजा सज्जा की ब्लॉकबस्टर फिल्म हनु मान का सीक्वल होगी।

मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित और टी-सीरीज द्वारा प्रस्तुत, जय हनुमान निर्देशक वर्मा के पीवीसीयू यूनिवर्स का हिस्सा है, जिसमें शेट्टी भगवान हनुमान का किरदार निभाते दिखेंगे।

फिल्म को कलियुग में स्थापित एक हाई-ऑक्टेन एक्शन गाथा के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जो हनुमान की अटूट भक्ति, निष्ठा और शाश्वत शक्ति को दर्शाएगी और उन्हें एक अमर आत्मा के रूप में प्रस्तुत करेगी।

इसकी शूटिंग इसी साल मार्च से शुरू हुई थी, लेकिन रिलीज तारीख का ऐलान होना बाकी है।

मिर्जापुरः द मूवी का ट्रेलर जारी, मुन्ना भैया-गुड्डू पंडित के बीच दिखा गद्दी का असली संग्राम

इंतजार खत्म हुआ। मिर्जापुरः द मूवी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। यह फिल्म प्राइम वीडियो की पॉपुलर फ्रैंचाइजी को बड़े पर्दे पर ला रही है, जिसमें पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु अपने पसंदीदा किरदारों में वापसी कर रहे हैं। रवि किशन, जितेंद्र कुमार और सोनल चौहान भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। ट्रेलर में फिल्म की एक लंबी झलक दिखाई गई है और इससे फैंस को पता चलता है कि स्ट्रीमिंग सीरीज से सिनेमा तक के इस सफर में क्या-क्या देखने को मिलेगा।

मेकर्स ने मिर्जापुरः द मूवी का धांसू ट्रेलर रिलीज किया। इंस्टाग्राम पर इसे साझा करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, गद्दी ना तो विरासत से मिलती है, ना सियासत से। मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ बाहुबल से और टिकती है डर पे। मिर्जापुर की एक नई कहानी, बड़े पर्दे के लिए। मिर्जापुरः द मूवी का ट्रेलर आउट।

ट्रेलर की शुरुआत एक गद्दी से होती है। बैकग्राउंड में पंकज त्रिपाठी का डायलॉग गद्दी ना तो विरासत से मिलती है, ना सियासत से। मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ बाहुबल से और टिकती है डर पे सुनाई देता है। मेकर्स ने नई फिल्म को एक ऐसी कहानी के रूप में वर्णित किया है जहां गद्दी विरासत या राजनीति के माध्यम से नहीं पाया जाता है। मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ बाहुबली से और दिखती है डर पे।

मिर्जापुरः द मूवी को सीरीज के उलट बनाया गया है। फिल्म बनाने वालों ने इसे थिएटर में दिखाने लायक बनाने के लिए इसके विजुअल और एक्शन सीन, दोनों को और बड़ा और शानदार बनाया है। कहानी कई जगहों से होकर गुजरती है। यह पूर्वांचल की जानी-पहचानी गलियों से आगे बढ़कर राजस्थान के विशाल इलाकों तक जाती है। उम्मीद है कि यह फिल्म दर्शकों को एक नया सिनेमाई अनुभव देगा, साथ ही उस दमदार माहौल को भी बनाए रखेगा, जिसने इस फ्रैंचाइजी को इतना पॉपुलर बनाया था।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित। शाखा कार्यालयः S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website : aryavartkranti Icom
*सम्पादकः प्रभात पांडेय सम्पर्कः 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail Icom